

ਫੇਰਾਈ ਲੁਨੀ

वर्ष 2012, अंक 19–20

प्रिय साथियों,

इस बार के अंक में हम लेकर आए हैं— अन्ना हजारे व ईरोम शर्मिला के संघर्ष की गूंज, आवास और विकास का सवाल, सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून, सूचना का अधिकार व लोकपाल पर खिंचती लकीरें, तथा आपके सुझावों के आधार पर शामिल कुछ सरकारी नीतियों व योजनाओं की सूची व संक्षिप्त विवरण।

आशा है विभिन्न आवाजों को समर्पित हमारा ये प्रयास आपके लिए उपयोगी रहेगा। अपने सुझाव व प्रतिक्रियाओं से हमारा प्रोत्साहन व मार्गदर्शन अवश्य करें।

नीतू रौतेला
जागोरी संदर्भ समूह

राजदीप सरदेसाई



अन्ना और इरोम

लेखक आईयीएन 18 ब्रेटवर्क
के पडिटर-द्वारा चीफ हैं।

[rajdeep.sardesai@
network18online.com](mailto:rajdeep.sardesai@network18online.com)

अन्ना और इरोम शर्मिला दोनों ही यूं तो अनशन का इस्तेमाल प्रतिरोध के एक शांतिपूर्ण सास्त्र की तरह कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे राज्यसत्ता के दुरुपयोग पर सवाल भी उठा रहे हैं।

दो आंदोलनों की दास्तान

मणिपुर वूमेन गन सर्वाधिकारी नेटवर्क की संस्थापक बीनालक्ष्मी

आप इरोम स्टार्टर्स के एक दूसरे से चल रहे अनशन का साथ पूछते हुए नेप्रेशन न मुझसे अनाम सुधारने की व्यवस्था का साथ पूछता। उत्तरी ही मुस्लिमों से बोया नहीं करत, जैसा आपने अनाम हजरत के तेह दिन के अनशन का बोया था? एक लाइब्रेरी प्रोफेसमें से ऊपर पर पूछता। इस अनशन से बच किनारों को कोई गुणाली ही थी। मैंने एक कमर्मना-सा जवाब दिया: शायद इमप्रेसन को तुमने यह मर्मालै देनां टीवी-टॉडियो के अधिक निकट है।

हर वह व्यक्ति,
जो एक सदाकृत
लोकपाल थिल
चाहता है, उसे
एकप्रकारपीड़ी के
उन्मूलन की मार्ग
का भी समर्थन
करना चाहिए।
और इसके लिए
अनन्त हजारे को
इरोम शर्मिला के
इस अनुष्ठान पर
विदाय करना
चाहिए कि ये
मणिषु आए और
उनके प्रति
समर्थन जताएं।

"दूरी की मजबूती", यह इस सवाल के लिए महज एक अपूर्ण समाज ही हो सकती है कि आईटी फोरेंसिक संस्थान पार्सिंस एक्सी (एपीएसपीए) के टन्डलन की मांग को लेकर नवंबर 2000 में अनशंख विवाद शुरू करने वाली एक 39 वर्षीय महिला के संबंधी दोनों टीवी चैनलों की सुधीखां बड़ी नहीं बनी। हाँ, यह मणिपुरी महिलाओं ने निवेदित होकर विरोध प्रदर्शन किया था, तब जरूर राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान कुछ समय के लिए इन अवधीं की ओर गया था। लेकिन इस मसले को पूर्णतया की परंपरागत उपेक्षा के चामे से देखना बास्तव में इस भी जटिल होकरका ही उत्तरांश करना चाहिए या डिजिटल और प्रबुद्ध नारायणों की नज़रों में "जनताक्रिक" प्रतिरोध के क्या मायने हैं।

एक क्षण के लिए इरम सर्पिल के साथ सूर्यों संवर्धन को भूल जाएँ और मेरे पाठक के बारे में चिकिता करो। इसी साल मई में पाठक ने पुस्तक में सूर्यों-ज्योतिशों को हटाया और उनके विशेषण में न दिन का अनश्वर चाहना चाहिया। उनके अधिकारीय अधिकारी का अन्य चाहना चाहिया था, लेकिन टीवी केरमे इफलात में नजर नहीं आता था। सूर्यों-ज्योतिशों को हटाया एक ऐसा मस्ता है, जो शाही मर्यादा वालों को असहज करता है। यह एक विश्वास पाठक को एक 'बदल मेंक' की तरह देखता है, फिर उसे वाघ परियोजना प्रभावितों के पुनर्वासी की मांग दी थी या शाही वासी में टाटा नामों पालन का विरोध। लेकिन वह एक सौ मेरे पाठक टीमों के अन्ना के मंच पर खड़ी होकर तिराशा फहरती है तो वे साहस व अदर्शवाली की प्रतिरक्षा बन जाती हैं।

या पिर लकड़ी-सामाजिक कार्यक्रम प्रशंसन भूषण के बारे में ही विचार करो। चंद्र मार्ग पूर्ण जग वे कार्यक्रम माझोबाबोंको के लिए केस लड़ते हुए थे या अन्यथा गांव की अधिकारीकी नियन्त्रण के लिए केस काम समर्थन कर रहे थे तो मीडिया के एक बांग ने उन्हें 'गणराज्यवर्षीय' करकर दिया था। आज यहाँ लीडीमीडिया उड़न्हें प्राचीनताके लिए दृष्टि कर रहे हैं योद्धा की तरह डूख रहा है। तब भूषण और पाटकर ने याचिकानी को चुनौती दी तो उन्हें निशाना बनाया गया, लैकिंजन जग वे धारा के साथ बढ़ने लगे तो उन्हें नामों-सा नामान् दिया गया।



वर्ष 1947

से पहले मणिपुर को
कांगलापाक किंगडम के
नाम से जाना जाता था।

इमफ्रल का कांगला फोर्ट 2004 से
पहले अद्वैतिक बल असम
रायफल्स का गढ़ हुआ करता था।

की सफलता की वजह थी उसका सरल और समावेशी चरित्र। यह एक ऐसा अंदेनन था, जो मेघा पाटक, श्रीरामवंश और अमृती के साथ ही लालूंग अनाम्ब भारतीयों को एक मंच पर ला सकता था। औदेनन यही अना और इपें शर्मिता के अंदेनन का भेद भी है। एक अंदेनन को सांगठित करने वाला माना जाता है तो उसका उपयोग इसके लिए करने वाला। एक आंदेनन महज जास्तीकालीन लिख के व्यापरे के बारे में ही नहीं था, भ्रातुराकार के विशुद्ध जन-मन में पैठे आकोरा का एक संस्कृत प्रतीक भी था। मध्य वर्षों के लिए अना का तपश्चार्यायूङ् अंदेनन उनकी अपनी उपभोक्ताकालीन जीवनशैली से विपरीत था, इसलिए अना टोपी घटनों का मात्रात्मक था, कुछ दूर के लिए थी, लेकिन एक संतुलन लिख के व्यापरों के लिए था। इस अंदेनन से आपका रुप से समृद्ध लोगों को सहस्र राजनीतिक रुप से भी सरक होने का आहसास कराया।

इसके विपरीत इरोम शर्मिला आम नाटकों के समझ एक अधिक जटिल विकल्प प्रस्तुत करती है। मणिषीयों के लिए वे एक स्थानीय नायिक हैं, जो जनों द्वारा उपलब्धिकारीयों के लिए विशेष की प्रतीकी बनती है। लेकिन देश के अन्य मायानायिकों की तुलना के अंतर्गत वे एक ऐसी संरक्षण के रूप में देख सकते हैं, जो भारतीय राज्यसत्ता की संप्रभुता को प्रश्नानिकृत कर रहा है। मणिषीयों लागू एकाकरणीयों की बुनियादी स्वतंत्रता का हठन करने वाली इकाई के रूप में देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत वे भी काम नहीं करतीं, जो उसे लाभदाता से प्रस्त बोल के लिए अलग-लग भागों। इन अंतर्गत में इरोम शर्मिला के अवसर को गद्यवाचियों द्वारा ठीक-

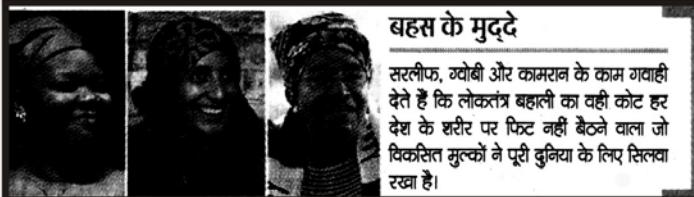
उसी तरह भारतीय राज्यसत्ता को एक चुनौती माना जाएगा, जैसे वे जम्मू-कश्मीर के किसी लोकप्रियतावादी अंदेलन को भारतीय संप्रभुता के लिए एक खतरा मानते हैं।

लेकिन विडंबना है कि अन्ना और हीरोम शर्मिता दोनों में ही कई समय अंतर भी हो सकते हैं। जहाँ दोनों ही अनशन का विवरण प्रतीतों के एक शारीर्पूर्ण शर्क तक तरह रखा गया है, वहाँ वास्तव में वे राजस्थान के दुर्घटयोग से प्रवालीयन करना भी लगा रहे हैं। सत्ता के दुर्घटयोग की बजाए कुप्रशस्ति। जहाँ सुरुस्थान विषयक ही जाता है, वहाँ भृष्टाचार की विषयक व्यापारी है। वहाँ मणिपुर ही या जम्मू-कश्मीर, एफएससीएस जैसे कानूनों को लाया करना वास्तव में एक प्रशासनिक संकरण को दर्शाता है। वस्तुतः मणिपुर और जम्मू-कश्मीर ने इसका कारण उत्तरां कट नहीं सहा है, जिन्हाँने भृष्ट गवर्नरी के लिए काम किया।

इसीलिए हर वह व्यक्ति, जो एक सशक्त लोकपाल बिल की प्रयोग करता है, उसे एपराक्सिपीये के उन्मुक्त की मांग का भी समर्थन करना चाहिए। और इसीलिए अना हजार को गधेरात्रावृक्ष इरोम शमिल के इस अंतर्राष्ट्रीय पर विचार करना चाहिए कि वे मधिराय और और उनके संबंध के प्रति अपना समर्थन चाहते हैं। यह पूरी तरह प्रतीकात्मक है, लेकिन इससे यह जरूर होगा कि टीवी कैमरे प्रायः प्रतीकात्मकी की ओर रुख करने को भी विचार हो जाएं, चाहे एक दिन के लिए ही सही।

ધ્યકન શ્રીપદુષ

लेखक सीएसडीएस से
संबद्ध हैं।



बहस के मट्टे

सरटीफ, योद्धी और कामराल के काम गयाही देते हैं कि लोकतंत्र बहाली का वही कोट हर देश के शरीर पर फिट नहीं ढैंठे वाला जो विकसित मुक्तों के पूरी दुनिया के लिए सिल्लवा सखा है।

अ बसे पहले क भी-क भार ही सुनने को मिला है कि अप्रीका का मध्य-पूर्वी की किसी महिला को नोबेल शानि पुरस्कार हासिल हुआ। 2004 में पहली बार अप्रीकी महिला को इस पुरस्कार के लिए सम्मान गया। उस समय केवल एक पर्यावरणवादी वांगी मथैयां को नोबेल शानि पुरस्कार से नवाजा गया था। इसी महीने मथैयां का देहांत हुआ है। मर्थांसे एक साल पहले शीर्ती ईंवाडी को नोबेल शानि पुरस्कार मिला था। सुधूर आश्चर्य कहा जाना चाहिए कि इस साल नोबेल शानि पुरस्कार का लेनाम हुआ है और उसमें अप्रीकी मध्य-पूर्वी की महिलाओं का नाम है। नोबेल शानि पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली 1 करोड़ रुपीड़ियों को लेने वाली 1 लाख यूरो में इस साल तीन महिलाएं हिस्सा बटा रही हैं। इनमें दो लेनन जानसन सलालों (लाभवर्तीयों को शामिल) और लीमा बोवों (सामाजिक कार्यकर्ता) परिचयी अप्रीकी के देश लाइंबिरिया की हैं और राशा नाम यमन की एक विद्युत प्रकार तकनीक कार्यालय का है।

नोबेल शास्त्र पुरस्कार से नवाजा गई शक्तियों में महिलाओं के नाम गिनती के हैं। सरलीफ, घोड़ी और कारमान के नाम शास्त्रिय कर लें तो भी इस सूची में महिलाओं की संख्या 15 पर जाकर थम जाती है। अफ्रीकी महिलाओं का नाम संख्या 25 पर जाकर थम जाती है। महिलाओं का नाम संख्या 25 पर जाकर थम जाती है। अफ्रीकी महिलाओं का नाम संख्या 25 पर जाकर थम जाती है। रशनाचालिता की वहजान के सिलजाह से भी दूर नहीं तो नोबेल पुरस्कारों की फैलाई हजार से ज्यादा तांग नजर आयी। विभिन्न विद्याओं में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कारों को एक साथ समेट कर देखें तो 1901 से लेकर 2011 तक बस 44 वाली महिलाओं की रचनालिताको नोबेल पुरस्कार से नवाजा लायक समझा गया। चूंकि कवरीयों को 1903 में भौतिकी के लिए और ऐस्ट्रिंग 1911 में

रसायनशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला इसलिए कुल 110 साल के इतिहास में नोबेल पुरस्कार से नवाजी गंगमहिलाओं की संख्या 43 मानी जाएगी, न कि 44।

पराम्परा वैसे ही किसी के संर्वश्च और स्वतन्त्रता के लिया जाने के लिए कह मानक तय कर दिया जाये।

पुरुषों ने ताकि सभी के सम्पन्न और विचारात्मक सम्प्रसारण के साथ विचाराधारात्मक प्रसंग लाजिमी तौर पर युज़ जाते हैं। इस बारे के नेबेल शांति पुरुस्कारों के साथ यह बात खास तौर पर देखा जा सकती है। तीन महिलाओं को संयुक्त रूप से नेबेल शांति पुरुस्कार देने वाली समिति ने कहा कि समाज के हर स्तर पर होने वाले बदलाव-विकास को प्रभावित कर कर सकते हैं जास्तीर्णक मामले में जब तक पुरुष और महिलाएं बदलारी पर नहीं आ जाते तब तक तब तक दुनिया में न तो लोकतंत्र कायम किया जा सकता है न ही स्थायी शांति स्थापना को जा सकती है। समिति ने माना कि सलालीफ, घोबी और कारबायन को यह पुरुस्कार महिलाओं की सुधूरा और शांति-स्थापना के काम में महिलाओं की पूर्ण महादारी के अधिकार के उनके अहिंसक संरक्षण के लिए दिया जा रहा है।

दिया है इस जानकारी के लिए कुछ मानव संघर का भवित्व है। लाइब्रेरिया गुजरे तीस सालों में दो बार गृहशुद्धि चर्चण में आया है और 40 सालों की आवादी वाले इस देश में दौड़ लाख लोग इस हिस्सा की भैंट चढ़े हैं। यह अपने एकीकरण के महज चार साल के अंदर (1995 में) गृहशुद्धि की चर्चण में आया और वहाँ ग्राहीजी अंदुकुल सालों हांगे को ही से हानिकार करने वाले बनाव-विकास कहा जाता है कि यमन शैश अंतर्गत से मानव-विकास के सुचकांकों के मामले में पीछे है या जब लाइब्रेरिया ही नहीं ज्यादातर अफ्रीकी मुख्लियों के बारे में संयुक्त र संघ की रिपोर्टों को मानकीकृत भाषा में सुनाया जा है कि वे मानव-विकास सूचकांक पर दुनिया के सब देशों ने यादवन के देश हैं तो इस अधिकार विद्यालयों में या राजनीतिक संदर्भ द्वारा यादवों द्वारा लोकान् बहाली के लिए अभी मालक आवृद्ध ऐडा नहीं हैं।

खुद को विकसित मानने वाले मुल्कों को लोकतंत्र और सच्चे लोकतंत्र के परख की कसीटियों की बात अवसर एशिया और अमेरिका के देशों के संबंध में यद आती है। यहाँ गरं करते ही लोकतंत्र की स्थापना एवं प्रारूपण की बराबरी की बात नावेल शांति पुरस्कार देने वाली समिति और इसके काणे इन देशों की सम्बति में छुट्टे हैं। लाइबेरिया की ग्राहपति एलन जॉन्सन सरलीकृत असामाजिक कार्यकर्ता लीमा ग्वाली हों या फिर व्यग्रन अंदरवालधी व्यक्तकर ताकूल कार्यालय- सबके यह स्वाक्षरिता में लोकतंत्र बहाती ही सभावनारीशत एंजेंट

रूप में चिह्नित किए जाते और पुस्तकारों के योग्य माने जाते हैं। किसी को यदि तक नहीं आता कि लोकत्रंत्र के जो मानक विकसित दुनिया शेष विश्व के लिए उपलब्ध है वही मानक उस पर भी लागू होते हैं। पल भर को मान लें कि स्टी-पुरुष के अधिकारी की बाबरी के मामले में लालौरिया या यमन की सांस्कृतिक आबाहा को अभी दुरुस्त विद्या जाना शेष है और यह काम सलालीक, खोबी-खोबी करकाराम अपने तक्क कर रहे हैं। पिर भी यह सवाल तो उड़ाया ही कि क्या विकसित दुनिया स्टी-पुरुषों के अधिकारों की बाबरी की मामले कर कर चुके हैं ?

सरलीक, खोबी और कामरान के काम इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतंत्र की बहाली का वही कोट हर देश के शरीर पर पिछ नहीं बढ़ने वाला था जो विकासित मुक्तों ने पूरी दिनिया के लिए अपने नाप के हिसाब से सिल्वा रखा। ऐसा ही गुहार से त्रस लालबारीमें खोबी की महिलाओं को इस बात के लिए तैयार किया जब तक शास्त्र-स्थापना की चाराएं किसी संतोषजनक मुकाम तक नहीं पहुंच जाती तबतक इस मिशन के लिए संघर्षतंत्र कोई भी महिला अपने परित से शरीरीक संर्पण नहीं बनाएगी। यथन के राष्ट्रपीठ सालों के खिलाफ तबहूल कामरान की महिला-प्रकरणों की संस्था 'खिला फें' को धरने में तनिक परहेज नहीं कि उसके बैचारिक रिसो 'मुसलिम बद्रहुड़' जैसे धर्मप्रेरित राजनीतिक संगठन से हैं। खोबी का प्रयोग एक दसर पर सत्याग्रहियों के लिए महात्मा गांधी की ब्रह्मचर्य-विधान की याद दिलाता है और लालबारिया की सांस्कृतिक परिवेश में ही संभव है। इसी दर यदन में लोकतंत्र की बायारी की सेकुलरी वातावरण से नहीं बदल जाएगा तब तक उसके लिए 'मुसलिम बद्रहुड़' की खिल्की का होना एक

जरूरी शत है। विडंबना यह है कि कामरान और खोबी जिस बात को पहचानती हैं, उन्हें पुरस्कृत करने वाला विकसित जगत उसी बात को लोकत्रैं के कच्चेपन का कारण बताता है। chandan@csds.in

chandan@csds.in

महाराष्ट्र में ‘नकुशा’ बनी ‘ऐश्वर्या’

अर्थोक वानखडे

बीते शुक्रवार की भाई दूज महाराष्ट्र के सतार जिले की 222 लड़कियों के लिए खास मानने रखी है। क्योंकि जीवन में पहली बार भाई दूज के त्योहार पर भरे ही से न हों, लेकिन दूसरे के रिश्ते के भाई भी उहैं उनके अपने नामों से पुकारे।

ये 222 लड़कियां हैं, जिनका नाम उनके जन्मदिन माता-पिता ने 'नकुरा' रखा था। 'नकुरा' कोई नाम नहीं, बल्कि एक मरणी शब्द है, जिसका मतलब है अवधिक वया अनवाही। 222 नजिकीयों को मतलब एक दूसरे से मिलती जुलती है, जबकि उनका परिवेश एक है, उनके परिवर्त की सामाजिक स्थिति एक है और उनका नाम एक है 'नकुरा'। राज्य सरकार ने 30 सितंबर को सतारा में एक कार्यक्रम आयोजित कर इन लड़कियों का नामकरण किया। 222 में से एक लड़की का नाम 'सुनीता' रखा गया और वास्ति 221 लड़कियां बनी 'ऐशव्यी'।

महाराष्ट्र में लड़के और लड़कियों का अनुपात जो 2001 में 1000 लड़कों पर 913 लड़कियों का था, वह 2011 में घटकर 1000 लड़कों पर 883 लड़कियों का हो गया है। यह जिस जिले का जिक्र चल रहा है, उसमें सभी जिले में तो यह अनुपात 1000 लड़कों पर 881 लड़कियों का ही है। समाज में वश जलने के लिए बेटा होना जरूरी माना जाता है। बेटे की ओरसे में एक के बाद एक बच्चों को जन्म दिया जाता है। जब घर में पहली सतान लड़की होती है तो परिवार इस सम्मानी मनता है कि वह एक बाल का आपानग ढुगा है। उसके बाद उसके भाई यानी लड़के के जन्म का इतराह होता है। लड़की के बाद फिर लड़की होती है तो परिवार इस संघर्ष से उसका स्वागत करता है कि पहली बेटी की बहन आई है। जब तीसरी बार लड़की पैदा होती है तो परिवार इस आस आप उसका स्वागत करता है कि यह अपने खाइ के अने की खबर लेकर आई है, लेकिन जब चौथी सतान भी लड़की पैदा होती है तो घर में मायमी छा जाती है। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में उस चौथे बच्चे के जंम पर न जश्न होता है न ही उसका नामकरण किया जाता है, जैसे कि उसकी बड़ी बच्चों का होता है। अंत में उसे नकुशा कह कर सम्बन्धित किया जाता है और जीवन के अंत तक वह अनवाही होने का सामाजिक दाम अपने ऊपर लेकर जीती है। नकुशा को स्कूल में भी नकुशा के नाम से

ही भर्ती किया जाता है और तब से कानून उसका नाम
नकुशा हो जाता है।
सतारा जिले में जब नकुशा हूँडों का अधियान चला तो
जिले के कारोबार और वाह इह तहसील में एक भी नकुशा नहीं
मिला। तथा तहसील में 92, माण में 56, कराड में 16,
महाबलेश्वर में 12, सतारा में 11, फलटन में 11, खंडवा

में 11 और जावती तहसील में 5 नक्शियां मिलीं। यह एक विडब्ल्युए है कि 125 साल पहले जिस महाराष्ट्र में नवीताबा और सावित्री बाबा फुले ने सामाजिक क्रांति की नींव रख महिलाओं के उथान के लिए काम किया था, आज उसी मार्ग पर लैन्सिंग गवर्नरी को पार्श्व मिला है।

सतारा जिले की एक शिक्षिका नकुशा किंदत अपने मां बाप की तीसीं संतान थी। उसके जन्म के बाद उसे नकुशा कहा गया। उसी नाम को लेकर वह स्कूल और कॉलेज तक। अब वह परिवार की एक मात्र संतान है। उसके शादी से चुकी है और वह दो बेटों की माँ है। उसका भी नामकरण हुआ। अब वह नकुशा से श्रृंग हो गई। नकुशा किंदत की चाह भी ऐसी जब उसके घर बाहर होगी तो वह उसका नाम श्रृंग रखेगी। बेटी तो उसके नाम से नहीं आई। इसके बाद उसने वही नाम अपनाया। जो उसने अपने बेटी के लिए सोचा था। सतारा जिले के पास पुणे जिले के नहे गांव की सरांच नकुशा भूमध्य सत्र बहनें हैं। उसका जन्म तीन बहनों के बाद हुआ तो उसे नकुशा कह कर संबोधित किया गया। शादी के बाद भी समरुद्ध बनने के बहु बहु नकुशा बनी रही। गांव की सरपंच बनने के बाद भी उसे उन्हें नकुशा ही जानी रही। कुछ महीने पहले गांव वालों ने अपने सरपंच का नामकरण किया। नकुशा भूमध्य अब जयश्री भूमध्य के नाम से जीनी जाने लगी। जयश्री बनने के बाद नकुशा ने इस बात का शिक्षिका की नकुशा नाम की बदली ही तो पड़ गई थी, लेकिन हमेसा अनचाही होने का दुख उसे सताता था। जिससे अब उसने कुट्टकरा पाया।

यह एक विचार संस्थान ही कहलाएगा कि 222 नक्शा जिस जिले में पाई गई थीं सतारे मराठों की राजधानी बनाया। छत्रपति शिवाजी ने वहां से बाज़ बढ़ावा महिला ही थीं। अनेक जम्म के पहले ही अपने पिता से दूर शिवाजी के उत्तरी भाग जीजावाई ही इस लायक बनाया कि उन्हें मराठा स्थाना की। आज उत्तरी छत्रपति के सतारे में लड़कियों को नामकां कह कर संबोधित किया जाता है। लेकिन अनचाही को चाहती बनाने का राज्य सरकार का यह कार्यक्रम तारीफ के कानिल है।



अब बिना डर के जीना सीखेंगी महिलाएं

आवाज उठाओ मुहिम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू

अमर उजाला ब्यूरो

गीत कॉलेनी। 90 फीसदी महिलाएं रजनामी को असरक्षित हैं। इस योजना के पाठे जागो री संस्था का एक सर्वे मुख्य रूप है।

क्या है योजना

गामाजिक सुविधा संगम की देशक श्यामी सोदी ने योजना की तात्पत्ति देते हुए बताया कि इस योजना को मूल रूप से निवेशिया चलाएंगी। इनमें वाल विकास विभाग, नियारसी (जैडर रिसोस सेटर) व यागों गी सम्म होगी। पायदृढ़

जेकर के रूप में पिलहाल 15 जीआसी यह कार्यक्रम चलाएगा। ह जीआसी महिला व पुरुषों समूह बनाएगे, जोकि कालोनियों महिलाओं के लिए महाल देखेंगे और उसमें सुधार नवराणी है। इस समूहों को ट्रेनिंग देने की योजनाएँ जागा री संस्था को तोड़ देंगी।

ज्ञानेंद्र रावत

दे श में तेजी से हो रहे शहरीकण और बहुमतिली अटटालिकाओं की बढ़ती तादाद के बीच जिस गति से मनवानगरों में झूँगियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है, वह चिंता का विषय है। सरकार ने प्रियते वर्ष दाव किया था कि अपेक्षा वर्षों में राजीव गांधी आवास योजना के तहत देश को झूँगी राजा लिया जाएगा। लेकिन यदि यही हाल रहा, तो अपेक्षा वर्षों में देश को झूँगी मुक्त करने का सरकारी दाव टांय-टांय किससे हो जाएगा।

झुगियों में रहने-बसने वाले गरीबों को अकसर बोझ की तरह देखा जाता है, जबकि इसी के श्रम के बलबूते शहरों का नवीनीकरण संभव हुआ है। दूसरों के रहने-बसने के लिए इमारतों का निर्माण करनेवाले

ये मजबूर खुद द्युगियों में
जीवन की मूलभूत सुविधाओं
के अभाव में रहने का मजबूर
है। उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने
की बात का तो सवाल ही
कहाँ उठता है।

आज देश में झुग्गियों में रहने वाले लोगों का आंकड़ा नौ करोड़ के पास पहुंच चुका है। जिकर वर्ष 2001 में यह संख्या सात करोड़ 52 लाख छह हजार की रकीवी थी। आंकड़े के अनुसार, देश की शहरी आबादी का एक चौथाई हिस्सा और महानगर का एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा झुग्गियों में रहने को मजबूर है। अकेले दिल्ली में आबादी का 17 प्रतिशत दिल्ली शहरी बीमारी 31 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं। चौथी अपेक्षा 25 प्रतिशत आबादी झुग्गियों में रहती है। यह आंकड़ा झुग्गियों में रहने वाले लोगों की

मर्जूदा सख्ता से संवाधत विभन्न पहलोंको जी जानकारी उपलब्ध करानेवाला आयोग के प्रमुख सलाहकार डॉ प्रबाल सन की अध्यक्षता वाली उच्च सरीरी समिति रेपोर्ट का है। देश के 3,799 शहरों कुल 5,161 शहरी क्षेत्रों में रहनेवाली आवासीय में सरकारी अधिक महाराष्ट्र में ही 1,81,51,070 लोग झुग्गियों का जीवन जीवन की कोरोना वैकृतिक है। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश का आता है, जहाँ 3,78,336 लोग झुग्गियों में रहते हैं। यह स्थान आज प्रदेश का है, जहाँ 38,022 लोग झुग्गियों में रहते हैं। चौथे पर मथुरा प्रदेश, 63,93,040, पांचवें पर हिमाचल, 58,022,022 और स्थान पर देश की यात्राओं दिल्ली है, 31,63,640 लोग झुग्गियों में रहते हैं।

फिर बिहार और उत्तराखण्ड का नंबर आता है, जहां क्रमसः 16,83,954 व 8,26,257 लोग झुग्गियों में रहते हैं। बिहार की राजधानी पटना में झुग्गी में रहने वालों की तादाद केवल तीन फीसदी ही बढ़ाई गई है, जबकि गैर-अधिकृत झुग्गियों में रहने वालों को उसमें शामिल ही नहीं रखा गया है। झुग्गी बसिटों की बढ़दली का आलम यह है कि वहां रिहाइशे, पेयजल, स्वास्थ्य-शिक्षा आदि की सुविधाएँ देने की जरूरत समझी नी होती जाती। बिहार देखिए कि इन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन पर्याप्त सुविधाएँ नहीं दी जाती। जो सुविधाएँ दी जाती हैं, वह एक्सान मानकर दी जाती है। अधिकांशतः शहरों में झुग्गियों में हनेवाले 40 फीसदी लोग असंरचित थे जो भजदूरी करते हैं।

अक्सर देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तरह ही इन शहरी ग्रामीणों के कल्याण का लिए बड़ी योजनाओं में स्वयंजग्गा पर जयादा जोर दिया गया, जिसका समरूपत लाभ इन्हें नहीं मिल सका। जबकि इनके लिए आवास

और सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता पर ज्ञादा जो देने की जरूरत है। वैसे सरकार का अब प्रयास है कि द्विगुण बस्ती की नई परिभाषा के अनुसार, मूलभूत ज़रूरतों से महसूस 20 से अधिक बचों की बसात को बस्ती माना जाए। इनके अलावा यहाँ में भी द्विगुण बसियों की गणना की जाए, जहाँ 20 हजार से कम आबादी है। राजीव गांधी आवास योजना की सफलता तभी संतुष्ट है, जब इसका सटीक अकाल हो। शहरी आवास व गरीबी उम्मति बनायी रखने जरनल कार्यालय के साथ एक समिलक काम करे, तभी द्विगुण बसियों की पहचान हो सकेगी।

अब द्विगुण बसियों में रहने वालों के नए अंकड़े भी खूब हैं, इनमें यह देखना होगा कि सरकार द्विगुण बसियों में हर साल जनसंख्या में दो साथ संतुष्ट होती रही कैसे रोकने में समर्थ होगी। अनुमान है कि वर्ष 2017 तक में 10 कोडे 44 लाख लोग द्विगुणों में रहने वाले होंगे। यदि ऐसा हुआ, तब समस्या और विकाराल हो जाएगा।

साल भर बाद भी पेयजल के मानवाधिकार अधूरे

सुभाष गाताडे

लेखक वारिष्ठ
पत्रकार हैं।

१ स्वच्छ
सुप्राप्ति को बुझा
जाने की पक्षी
आयोगों में दृढ़ा
छोटा सा पुलक
ददक में पानी
समूहों को सो
दुनिया भर में
कृचाचामा न
प्रसिद्धिलाल
भ्रताल आ ग

काम में
कार्पोरेट समूहों
के बारे व्यापक
होते दिख रहे
हैं।

संयुक्त गणपंथ की आम सभा द्वारा बहुत से सच्च पैने के पानी एवं सैनिटेशन तक सुधारता को बुनियादी मानवाधिकारों में युझार किए जाने की पहली सालगिरह (28 जुलाई) पर हुए आयोजनों में सबसे आगे रहा लातिन अमेरिका का छोटा-सा मुल्क बोलीविया। इक्कीसवीं सदी के पहले दशक में पानी के वितरण आटा को विशेष कारोबार मध्यमों को सौंपने वाला था। उन्हींने उन्हींने भर्म और बोलीविया ने नवीन कार्रवाई की है। कूचाचाम्बा नामक शहर के पानी उद्योग को जब प्रासिसी कंपनी को सौंपा गया था, तब पूरे मुल्क में भूचाल आ गया था।

जब आम सभा में प्रस्ताव रखने की बारी आई तो उसे बोलीविया के गजदूत ने ही 33 देशों के सहयोग से रखा। पिछले साल जब आम सभा में इस प्रस्ताव पर मतदान हुआ था तभी वहां उपर्युक्त 41 रेस -जिनमें से अधिकतर ऑस्ट्रेलिया थे - ने मतदान में भाग नहीं लिया था। यहां तक कि संघरण गज अमेरिका, कनाडा और विटेन ने प्रस्ताव

पर वोट डाले जाने का ही विशेष किया। आज की तारीख में दुनिया भर में 90 कांगड़ लोग सुरक्षित एवं साफ़ कांगड़ के पानी से बचत हैं और 10 कांगड़ लोगों के पास बुनियादी की कोई सुरक्षा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र द्वाग संस्कृति अकाड़ बताते हैं कि पानी एवं सौनिटेशन की कमी से जुड़ी बीमारियों के चलते हर साल 15 लाख बच्चों को पांच साल के अंदर ही मौत हो जाती है।

यह सवाल पूछ जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की आप सभा की इस निर्णय को क्या कानूनी ढंग से लागू करवाया जा सकता है? नहीं। यहाँ जिस संविधान के निवारणी को नियन्त्रण भेदभाव से रखता है, जिस तरह लोगों के लिए भोजन का अधिकार है, उसी कड़ी में इस अधिकार के जुड़े-के क्या मायने हैं?

निश्चित ही प्रतीकात्मक तरीके पर इसको बहुत अधिकायत है, जो इस बात को रेखांकित करता है कि विषय की बढ़ती आवासों के लिए पानी की कमी कितना बढ़ा उत्तर मसला बना है। यह प्रस्ताविक विधिन गणितीय संस्करण पर इसे पूरा करने की अधिक जिम्मेदारी लाता है।

पानी की कमी और कषीयायम् जमीनों के रेखांकित

बनने की परिस्थिता पहले अप्रीकाएं वैश्याशय को समस्या समझी जाती थी, मगर अब यूरोप को भी इसे झेलना पड़ रहा है। दक्षिण स्पैन में हाजा साल रेगिस्ट्रेशन उत्तर की तरफ एक किनोव्होर बदला है। इसके अलावा पानी की कीमतें चलते ग्रीष्मीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए विवादों की जमाने बनती दिख रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों की पहल पर पानी की आपूर्ति के निजीकरण ने समस्या को और गंभीर बनाया है जिसके चलते हाजा साल ग्राहकों को अधिक क्रौमत देने पड़ती है।

जहा तक गुरुभाना दिल्ली का बात है तो यह देखा जा सकता है कि वह पहली साल हिंग नारायण के लिए बेहद पवित्र समय पर आई थी क्योंकि यही वह दौर है, जब पानी के निकायकाम के जरूर इस अधिकार को कमज़ोर किया जा रहा है। 'पर्लिक्प्रायवेट भगीरथार्ग' के नाम पर पानी के वितरण, सेवाओं के प्रबंधन तथा बाटर टीवीएट प्लाट से खरखराव को कारपोरेट समूहों को सोंचा जा रहा है और इसके लिए तर्क वर्धा दिया जा रहा है कि यहाँ की कमी है। इस समस्या को संबोधित करने के लिए न समान वितरण, न रेनबॉर्ड हॉस्टिंग, न ऐसा कोई कदम उठाया जा रहा है जिससे पानी की

बत्तवादी रुक सके। हाल में यह तथ्य उजागर हुआ था कि दिल्ली जल बोर्ड का आधा पानी यूं ही बह जाता है। निश्चित ही पानी के निकारण को पूरे बड़ी में लागू करने की नीति से अलग नहीं माना जा सकता। सभी के लिए अच्छ एवं सफ सपानी उपलब्ध करने में यजम की नाकामी ने ऐसी स्थिति पैदा की है कि पानी को लोगों तक पहुंचाने के काम में कापेरिट सर्वांके के बारे न्यारे होते दिख रहे हैं।

गोरतलता है कि पाना के निजीकरण के खिलाफ देश के अलग-अलग हस्तों में ही नहीं बल्कि बोलतीविया, इट्टी जैसे मुकुट में जबरदस्त संघर्ष चलते हैं। कई दोष देश जिन्होंने पानी के निजीकरण को अंजाम दिया था, उन्हें सार्वजनिक नियंत्रण और वितरण की तरफ लौटाया पड़ा है। जून माह में इट्टी के एक जनमत संग्रह में पानी के निजीकरण को खारिज कर दिया गया। इस साल फरवरी में, कनाटक के अलग-अलग नगरों के लोगों ने बोलार्थी में एकत्रित होकर निजीकरण का विरोध किया। उनके विरोध का ही नतीजा था कि कनाटक सरकार को यह कहना पड़ा कि वह अपेक्षित ड्रेनिशन के प्रतिनिधियों से मलतकान भी नहीं करेगी।

subhash.gatade@gmail.com

ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी के रंगीन सपने

हजारों, नार निगम की नलों से बैद्ध तपती धारों में बहते पानी को अपने-अपने बर्तनों में भरने के लिए लड़ती-गङ्गाड़ी महालियों और बीड़ी की थुके द्वारा साथ महल्ले की समस्याओं को हवा में उड़ाते बुजुर्गों में से शायद किसी को भनक भी नहीं लगी और बच्चों ने मोहल्ले की तसरफ़ ही बदल दी। अब उन्हें लगें लागा है कि तकदीर भी

शा यद उनकी ममता
दीदी को बचकानी
लगे यह बात, लेकिन
कुछ बच्चे पूरे कोलकाता का नशरा
बदल देना चाहते हैं। बच्चों की इस
दिन से आकर लेना शुरू कर दिया
है। और शुरूआत ही है कैलकाता
की ऋषि अविंदो कालोनी से।
कोलकाता के पूर्वी इलाके में रेलवे
लाइन से सटे लगभग नौ हजार की
आबादी वाले इस मोहल्ले में जिटा
रहने का एहसास आयकर की
सीमाओं में है या नहीं, इस पर बहस
हो सकती है या नहीं, अब इस
बात में विसिनी को शक नहीं कि
उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। छोटे-
छोटे बच्चों ने भिलकर ऋषि अविंदो
कालोनी को पूरी दुनिया के सामने
ला खड़ा कर दिया है। सुबह टिप्पण
लेकर काम पर निकलने वाले
बाबूओं, पट्टी पर कच्ची सब्जी
लेकर बैठने वाले अन्यायों,
इटालियन सेलन पर काम करने वाले

में पढ़ने वाली बच्चों की प्यारी दीदी अपर्णा दास को भी बच्चों ने बुलाया। कोई स्कैच लाया, तो कोई कागज। कोई डॉकर सेलोटेप ले आया, तो किसीके हाथ में कैची थी। मोहल्ले के चर्चे-चर्चे से वाकिफ बच्चों ने अपना काम शुरू कर दिया। काम आसान नहीं था, लेकिन उत्साह आसामान में था। एक ने बनाया, दूसरे ने मिटाया। कई कागज बचाया हुआ। कई इग्नोर हुए। रुक्ने और मनान का दौर चलता रहा। और अब बच्चों की इस प्रवास पर इनके में बच्चों से काम कर रही एक स्वर्यंशील संस्था

तंग गलियों में रहने वाले
कॉलकाता के उन बच्चों
ने अपनी कॉलेनी की
पहचान को पुख्ता करने
के लिए जो मैप तैयार
किया है, उससे
नगरपालिका को भले ही
शर्म आ रही हो, लेकिन
दुनिया भर से मिल रही
है ——————।



मैप के लिए डाटा जुटाते प्रयासम के बच्चे

प्रयासम्' की नजर पड़ी। प्रयासम् के प्रोग्राम आफिसर प्रशंसन रूप और डायेक्टर पाली मञ्चमुदार वे बच्चों की जित को सही आकार देने का फैसला कर लिया। ये वही बच्चे थे, जो प्रयासम् के एकजूट और निर्णायक में शरीक होते रहे थे। टास्क कठिन था, लेकिन अब इस काम में यूनिसेफ भी बच्चों की मदद के लिए आ गया था। अब बच्चों के पास साधन था। गूल अर्थ मैप से मदद ली गई। धीर-धीर एक सही और कूम्हमल नक्शे ने आकार लेना शुरू कर दिया। पहले बच्चे परामर्श दिया कि मैपींग टर्म्स का इस्तेमाल करते थे। बाद में बच्चों के इस काम को देखते हुए कोलेक्टिवा यूनिवर्सिटी अध्यक्ष इंटीट्यूट के मैट वर्न बच्चे से मिल और मैपिंग के लिए खास तौर पर तैयार किया हुआ तीन-मोबाइल फोन बच्चों को भेट कर दिया। खास तह के उस मोबाइल फोन ने बच्चों के काम को बेहद आसान कर दिया। घर-घर जाकर बच्चों ने जीपीएस सिस्टम से लैस उस मोबाइल में घर में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी उम्र, आय के साथन और साथ्य संबंधी परेशनियों को दर्ज करना शुरू कर दिया। बच्चों की सेवनत रोल लाई।

के 'मुहान' पर छोटी सी दुकान चलाने वाला बैकिम थोक पहले सलीम को देखते ही भुग्पत्राता था— अस्तो बोका ! 'एक सलीम को लेने पर काम हो गया है,' पूछते जो बोलते संझे होते हैं। और सलीम सचमुच बड़ा हो गया है। कहता है, 'पूरे कोलकाता का ऐसा ही नवाहा होना चाहिए।' लेकिन वाहां के तेज शोर में भी रॉयली संगीत सुन लेने का जुगाड़ कर लेने वाले महानारायण कोलकाता को शायद पुरस्त नहीं कि घर एक बेहद पिछड़े और दबू किस्म के मोहल्ले में रहने वाले समझने और उत्तरके दोनों की बातों पर धौकाएं करें।

ताने को पर बेबा। गा ऐसा

गरीबी के मानक तय करने में मील के पत्थर...

- भारत में गरीबी के परिमाण के निर्धारण के लिए लम्बा समय बीत गया।
- एक ऐसी गरीबी रेखा की परिभाषा, जो गरीबी की हृद के सही आकलन की इजाजत दे, के तय करने की वेष्टा का न्यायपूर्ण ढंग से एक लम्बा इतिहास है।
- वी. एम. दांडेकर ने 1996 में इस सम्बंध में चार युक्तियां सुझायीं थीं- जरूरी उपभोक्ता वस्तुओं, खासकर खाद्य पर एक गृहस्थ या गृहिणी के द्वारा किये जाने वाले खर्च का औसत, खाद्य का कैलोरी मान, संतुलित भौजन का मूल्य और आदमी के अस्तित्व के लिए न टाले जा सकने वाली आवश्यक वस्तुओं का मूल्य। ये उपाय अधिक सुरंगत और व्यावहारिक लगते हैं। बहरहाल, इस दिशा में प्रगति उपर्योग पर एक नज़र।

जीवन बसर लायक गरीबी रेखा :

- भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए सबसे पहला कदम आजादी के पहले दादा भाई नौरोजी का था।
- इसके तहत खाद्य पदार्थों की 1867-68 की कीमतों के आधार पर गरीबी रेखा तय की गयी।
- इसमें शांत राज्यों में प्रवासी कुलियों को दिये जाने वाले आवश्यक पोषक तत्वों को आधार बनाया गया।
- ये कुली वे गिरमिटिया मजदूर थे जिन्हें समुद्र पार (परदेश में) काम के लिए ले जाया जाता था।
- पोषक तत्वों में चावल या आटा, दाल, मांस, सब्जी, धी, बनस्पति तेल और नमक को मुख्य तौर पर सम्मिलित किया गया था।
- इसका आधार भी उन कामगारों की तब के 16 से 35 रुपये के बीच घटती-बढ़ती सालाना प्रति व्यक्ति आमदनी थी।



जीवन निर्वाह का समुचित मानक :

- राष्ट्रीय योजना समिति (एनपीसी) के संघित के रूप में के. टी. शाह ने 4 जून, 1939 को एक नोट तैयार किया।

- इस नोट में उन्होंने लिखा कि "...मूल लक्ष्य (योजना का) देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों के जीवन-निर्वाह का समुचित मानक सुनिश्चित करना है।
- उन्होंने इसके लिए रुपये के वर्तमान के मूल्य के आधार पर 15 से 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह की आमदनी को आधार बनाया।



योजना आयोग के प्रयत्न :

- 1962 में योजना आयोग ने प्रतिचित अर्थशास्त्रियों के एक कार्यकारी समूह की नियुक्ति की जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में रुपये 20 प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में रुपये 25 न्यूनतम प्रतिदिन खर्च स्तर वाले मान के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए एक सेट की सिफारिश की गयी।
- इसका आधार 1960-61 की कीमतों को बनाया गया।

पहला सुनियोजित आंकलन :

- 1971 में वी.एम. दांडेकर और एन. रथ ने गरीबी के निर्धारण के लिए पहला सुनियोजित आंकलन आधार उपलब्ध कराया।
- इसमें राष्ट्रीय प्रादर्श सरक्षण (एनएसएस) के 1960-61 के आंकड़ों को आधार बनाया गया था, अलवता इसका विश्लेषण अलग तरीके से किया गया।
- इस मानक को खर्च की उस सीमा (कट-ऑफ) पर आधारित किया गया जो रोजाना प्रति व्यक्ति 2,250 कैलोरी की उपलब्धता सुनिश्चित करती हो।

श्रीनिवासन का फार्मूला :

- देश में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए एक ऐतिहासिक आधार उपलब्ध कराते हुए 2007 में टी.एन. श्रीनिवासन ने इस सम्बंध में विभिन्न कौशिंशों की पहचान की।
- श्रीनिवासन ने अपने कार्मिले में नौरोजी की इस मान्यता की तरफ ध्यान खेंचा कि गरीबी रेखा के निर्धारण में काम के लिए ऊर्जा, उसके न्यूनतम-सुख-साधन, सभी सामाजिक और धार्मिक अपेक्षाओं तथा सुख-दुःख के मौके पर होने वाले सभी खर्चों की जरूरत को सम्मिलित नहीं किया गया है।
- उन्होंने इसकी तुलना 2004-05 के लिए योजना आयोग के द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से करते हुए मुदासकीति के लिए सुधार किया।
- उन्होंने यह निष्कर्ष नहीं रखा कि 2004-05 के लिए तय सरकारी गरीबी रेखा नौरोजी की तय गरीबी रेखा से कहीं अधिक ठीक है।



स्रोत : इंडिया कॉन्सिक पॉवर्टी रिपोर्ट

जानिए : कौन है बीपीएल

- भीख मांग कर गुजर करने वाले
- बेघर परिवार
- मैला ढोने वाले परिवार
- आदिम जनजातीय समूह
- छुड़ाए गए बंधुआ मजदूर

बीपीएल में दी जाएगी जिनको प्राथमिकता

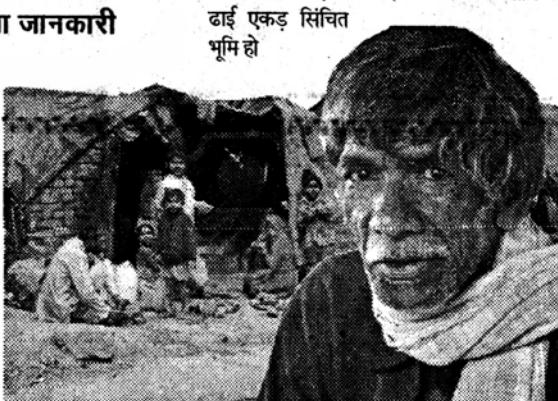
- एक कमरे के कच्चे मकान में रहने वाले परिवार
- जिस परिवार में 16-59 वर्ष का कोई वयस्क सदस्य नहीं है
- महिला मुखिया वाले परिवार जिसमें 16-59 का कोई पुरुष नहीं है
- अनुसूचित जाति-जनजाति के परिवार
- दिवाड़ी मजदूर जो भूमिहीन हैं
- सक्षम शरीर वाले वयस्क सदस्य से रहित परिवार जो निःशक्त है

बीपीएल से क्या-क्या जानकारी चाहती है सरकार

- व्यवसाय
- शिक्षा
- निःशक्तता
- धर्म
- अनुसूचित जाति-जनजाति
- धर्म
- जाति/जनजाति का नाम
- रोजगार
- आय और आय का साधन
- परिसंपत्तियां
- मकान

टिकाऊ और गैर टिकाऊ उपभोक्ता समाज

- भूमि
- ये बीपीएल नहीं माने जाएंगे
- जिन पर दो पहिया या चार पहिया वाहन हैं या मछली पकड़ने की नाव है
- मशीन चलित तीन या चार पहिए के कृषि उपकरण हैं
- 50 हजार का किसान क्रेडिट कार्ड है
- सरकारी सेवा में हो
- सरकार में पंजीकृत गैर कृषि उद्योग होने पर
- परिवार का कोई सदस्य 10 हजार मासिक कमाता हो
- आयकर देता हो
- व्यवसायिक कर देता हो
- सभी कमरों में पक्की दीवार हो या तीन कमरे हों
- फ्रिज हो
- लैंड लाइन फोन हो
- कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ ढाई कैड सिंचित भूमि हो



गरीबी हटाओ योजनाएं

रोजगार और स्व-रोजगार

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गरंटी कानून
- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना
- शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम
- शहरी मजदूर रोजगार कार्यक्रम
- महिला प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम सहायता

आधारभूत संरचना और बुनियादी सेवाएं

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
- इंदिरा आवास योजना
- सम्पूर्ण स्वास्थ्य अभियान
- भारत निर्माण
- जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण अभियान
- त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति
- समेकित जल संरक्षण प्रवर्धन कार्यक्रम
- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष

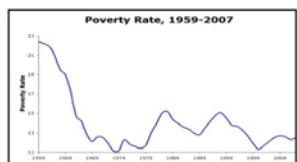
विशेष समूह के लिए कार्यक्रम

- अनुशृंहित जाति उप-योजना और जन जातीय उप-योजना
- समेकित वाल संरक्षण योजना
- राष्ट्रीय तुर्जुर्ग ऐशन योजना
- किशोरी शक्ति योजना

स्रोत : इंडिया कॉन्सिक पॉवर्टी रिपोर्ट

स्वास्थ्य और स्वास्थ्य बीमा

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान
- जननी सुरक्षा योजना
- राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रम-तीन
- आम आदमी बीमा योजना
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना





अधूरी तैयारियां

खाद्य सुरक्षा के लिए कानून के साथ इच्छाशक्ति की जरूरत

आ

खिकार खाद्य सुरक्षा कानून अब व्होकेट बनने जा रहा है। आजादी के बाद का संभवतः यह सबसे महत्वाकांक्षी कानून है, जिसका उद्देश्य देश के लोगों को भोजन उपलब्ध होने की गारंटी प्रदान करना है। इसके दारेरे में ग्रामीण इलाके की 75 फीसदी और शहरी रुदी गई है और मान लिया गया है कि जिनको दारेरे में नहीं रखा गया है, वे अपनी खाद्य सुरक्षा करने में खुद समर्थ हैं।

यह कानून जितना महत्वाकांक्षी है, इसे लेकर व्यक्ति किए जा रहे संघर्ष उठने ही जारी बढ़े हैं। देश की खाद्य सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे लोग एक तरफ अपनी नाराजी जाहिर कर रहे हैं कि इसके दारेरे में देश की पूरी आजादी को ख्याल नहीं रखा गया, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोगों की तादाद काफी है, जो मानते हैं कि यह एक ऐसा कानून है, जिसका पालन संभव ही नहीं है।

खाद्य सुरक्षा का मतलब है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकों यानी किसानों से अनाज की खरीद का पुख्ता इंतजाम, अनाज के भंडारण की व्यवस्था और उसके वितरण का उचित प्रबंध। इसमें अनाज के उत्पादकों को उनकी उपज का सही मूल्य उपलब्ध कराना और उपभोक्ताओं को सही दर पर अनाज उपलब्ध करने की इच्छाशक्ति और सामर्थ्य भी शामिल है।

सबाल उठता है कि क्या इस तरह की

तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? जवाब है— नहीं। अनें देश में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आवादी निवास करती है और संभव है कि अगले एक-दो दशकों में ही हम दुनिया की सबसे बड़ी आवादी बाला देश बन जाएं। हम दावा करते हैं कि हमने अनाज उत्पादन में अनाज निर्भरत प्राप्त कर ली है। मगर तथ्य यह भी है कि गरीबी के कारण हमारे देश की आवादी के एक बड़े हिस्से को भोजन भोजन भी नहीं मिल पाता।

उनकी क्रायशक्ति कम है। इस कारण हमारे देश में अनाज की जितनी खप्त होनी चाहिए, उन्नी ही नहीं पाती है और देश की आवादी का एक बड़ा हिस्सा कुपोषण का शिकार होता है। इस असुरुलन को दूर करने के लिए खाद्य उत्पादन में भारी वृद्धि करनी होगी।

आवादी के अनुपात में अनाज उत्पादन भी बढ़ाना होगा और भंडारण का इंतजाम भी करना होगा।

इस समय मिर्क इरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ही, वहाँ की स्थानीय जरूरत से ज्यादा अनाज का उत्पादन हो पाता है। इन राज्यों के सप्ताह से अन्य गरीबों के अनाज घाटे को पूरा किया जाता है। जाहिर है, यदि अनाज का उत्पादन बढ़ाया हो, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखण्ड और मध्य प्रदेश में अनाज का उत्पादन बढ़ाया पड़ेगा। इन गरीबों की जमीन उपजाह है, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था की कमी और बाढ़ के कारण अनाज उत्पादकता काफी कम है। पानी की बहुलता वाले ये प्रदेश, जो पर्याप्त से पिछली कई सर्वियों से भारतीय उत्पादकीय के सबसे समृद्ध इलाके हुआ करते थे, आज सबसे गरीब इलाके में उत्पादी हो गए हैं। यहाँ की भूमि और जल प्रबंधन और उसे ज्यादा अनाज उत्पादन के अनुकूल बनाने के लिए अर्द्ध-अब रुपये के निवेश की जरूरत है। पर वह निवेश की इच्छाशक्ति हमारे नीति निर्णयों में दिखाई नहीं देती।

खाद्य सुरक्षा की किसी व्यवस्था में किसानों की उंगली नहीं की जा सकती। उनका ध्यान रखने के लिए अनाजों के समर्थन मूल्य की व्यवस्था कायम की गई है, पर यह व्यवस्था सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। जब फसल कटी है, तो किसानों को समर्थन मूल्य से बहुत कम कीमत पर अपना अनाज बाजार में बेचना पड़ता है और इस तरह उन्हें मिल रहा



समर्थन उन बिचौलियों के काम आ जाता है, जो कम कीमत पर अनाज खरीदकर समर्थन मूल्य पर सरकार को बेच डालते हैं। प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर किसान आज आशक्ति है, तो इसका कारण यही है कि उन्हें लगता है कि उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अनाज उत्पादकता के नाम पर उनके उत्पादों के समर्थन मूल्य को भी सरकार कम रहीं और वे शायद लागत भी नहीं निकल पाएंगे। किसानों का यह डर करनेवाला नहीं है। जाहिर है, इस भय के माहौल में, न तो अनाज का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और न लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।

अनाजों की खरीद के साथ-साथ उसके भंडारण की समस्या भी देश में बनी हुई है। गोदाम नहीं मिल पाने के कारण अनाज सड़ जाते हैं, या सड़कों पर पड़ रहते हैं। भारतीय खाद्य निगम के केंद्रीय बैरब हाउस कॉमीटीशन के पास उतने गोदाम नहीं हैं, जो खाद्य सुरक्षा कानून को सफल बनाने के लिए पर्याप्त अनाज का भंडारण कर सके।

इस कानून के तहत जिन्हें सुरक्षा देनी है, उनकी पहचान का ममता भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने पहले बीपीएल कार्ड बनाया रखा था। वह कार्ड अब भी है, पर उसमें भारी कमियां हैं, और उन्हें दूर करने के लिए एक बीपीएल सर्वे, जिसे सामाजिक आर्थिक जनगणना भी कहा जाता है, चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खाद्य सुरक्षा आयोग द्वारा बीपीएल सूची तैयार करने की मांग कर रहे हैं, तो तमिलनाडु की मुखिया जयललिता उस गणना के मानकों से सहमत नहीं हैं और वह अपने राज्य को खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे से बाहर रखने की मांग कर रही है। इस योजना पर अलंक बनाने में मुख्य भूमिका राज्य सरकारों की ही होगी और उनके द्वारा की जा रही यह आपति शुभ लक्षण नहीं है।

इसके अलावा इसे सफल बनाने के लिए भारी पैमाने पर सर्विसदी चाहिए। क्या केंद्र सरकार सर्विसदी के उस बोझ को उठाने के लिए तैयार है? डर है कि इसका हत्रि शिशा के अधिकार कानून जैसा न हो।



घेरे से बाहर

खाद्य सुरक्षा कानून में 'प्राथमिकता' बीपीएल का ही दूसरा नाम है!

लं वी जदौजहद के बाद लोकसभा में खाद्य सुरक्षा विधेयक पेश किया गया। यूपीएसकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का जो मस्तौदी कैविटेनेट ने पास किया तो, वह कई सवालों को उनकी देता है। कहा है कि जो नहीं रखा है, वह उनके लिए आजादी को इससे लाभ मिलेगा। मगर यह साफ नहीं किया जा रहा है कि यहाँ सावधान में सवालों को 'प्राथमिकता' वाले परिवारों तक सीमित किया जा रहा है।

मस्तौदी के अनुसार, सिर्फ प्राथमिकता प्राप्त वरिवार ही समस्त अनाज के खलफार होंगे (यानी, तीन रुपये प्रति किलो तक सीमित) और रुपये प्रति किलो मोटा अनाज)। ग्रामीण क्षेत्रों में 46 फीसदी परिवार ही 'प्राथमिक' होंगे। 75 प्रतिशत नहीं। वाकी के 29 फीसदी परिवार 'सामान्य' सूची में रहे जाएंगे और 25 फीसदी कानून के दायरे से बाहर होंगे। सामान्य परिवारों को तीनों प्रति वरिवार ही अनाज का उपलब्ध किया जाएगा। इसके दूर नूनम समर्थन मूल्य से आधे दायरे पर, कमोबेश बाजार मूल्य के बराबर होंगे।

शहरी क्षेत्रों में भी पचास फीसदी आवादी इसके दायरे से बाहर होगी, जबकि 28 प्रतिशत प्राथमिकता सूची में शामिल होंगी और रुपये 22 फीसदी लोग सामान्य परिवारों में गिने जाएंगे, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से बाहर होंगे। गैर

किया जाए कि ग्रामीण (46 फीसदी) और शहरी (28 फीसदी) क्षेत्रों के प्राथमिकता सूची का ओकड़ा तेलुकर कमटी द्वारा तथ्य गरीबों की संख्या के असमरप्त पहुंचता है। यानी, इस कानून में बीपीएल परिवारों को नया नाम दिया गया है — प्राथमिकता परिवार। और एपीएल अब सामान्य कहलाएंगे।

ऐसा लगता है कि सरकार, और मीडिया भी, यह भूल गए हैं कि वितरण अवकूपर में ही सुधीरी कर्तव्य में देशी योजना आयोग के संयुक्त बयान जारी किया जाता है। वह बयान यह साफ नहीं कर पाया कि योजना आयोग द्वारा तथ्य गरीबी रेखा विचर्ता के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रसारित है, और उसकी सीमा क्या है। सरकार ने यह तो स्पष्ट किया कि वह बया नहीं करेगी, मगर वह बया करने वाली है, यह तब रहस्य रहा।

वह संयुक्त बयान भले ही मीडिया में चल रही बहस को शांत करने में सफल रहा, पर योजना आयोग के इस हस्तक्षेप को वास्तविकता से टाल-मटोल करने, दोतरफ़ा बातें बोलने और पलायन करने के रूप में देखा जाना चाहिए। मसलन, योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि मध्यांचल भोजन योजना, समन्वित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), मनरेगा, जैसी कल्याणकारी योजनाएं गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों तक संप्रित होती हैं। उन्होंने बड़ी सलता से उन लक्षित योजनाओं के नाम नहीं लिए, जो गरीबी रेखा के निर्धारण से प्रभावित होती हैं। जैसे पीडीएस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, विद्याएं और बुद्धिवास्तवा पेशन और कुछ हद तक ईंटिरा आवास योजना।

विगत मई में 40 अर्थात् सिर्फ ग्रामीण वितरण प्रणाली के लागू करने की व्यापक



को पत्र लिखकर गुजरातिका की थी कि खाद्य सुरक्षा को तकरीबन सार्वभौमिक बनाया जाए। पिछले दिनों ही सर्वोच्च न्यायालय ने 'भोजन का अधिकार' मामले के दौरान बहुते खाद्य भंडारण और उसके रख-खाल में आ रही परेशानियों को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया था।

योजिताकाकातीओं ने मांग की थी कि गोदामों में क्षमता से अधिक रखे गए खाद्यान का इस्तेमाल पीडीएस में किया जाए, ताकि अधिक से अधिक गरीब परिवारों को लाभ मिले। जैसे, अर्थात् गरीब रेखा दो सी जिलों में सभी को नियन्त्रित करने के लिए बढ़ती महांगी के दौर में सरकार जन वितरण व्यवस्था का विस्तार कर अर्थवा बाजार में खाद्यान की आपूर्ति बढ़ाकर, गरीबों को राहत दे सकती है।

पीडीएस के संदर्भ में यह भी एक सच है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान जैसी कई राज्य सरकारों ने इसका दायरा योजना आयोग की गरीबी रेखा से नीचे है, गरीबी जनगणना और चिल्हनाहीन होगी, लिहाजा एक अंतरिम मानक बनाकर सभी को यह दे दिया जाए।

गरीबी जनगणना से गरीबों को बाहर रखने के सुवृत्त और सार्वभौमिक स्तर पर अनाज वितरण को लागू करने की व्यापक

सरकारी गोदामों में क्षमता से अधिक रखे गए खाद्यान का इस्तेमाल पीडीएस में क्यों नहीं किया जाय सकता?



दो दफ

ज्यां देते

अथवीति

edit@amarujala.com

यही कारण है कि गोदामों में अनाज भरे हैं और गरीब भूखे मर रहे हैं

੩

झा खंड के लातेहार जिसे के डब्लू सिंह के परिवार की दुर्लभ वर्तमान खाई नीतियों की विसंगति को जितना मार्गिकात्मक से उजागर करती है, नीती शायद कोई और बात नहीं करती। दिल्ली मजदूरी पर निर्भर आदिवासी युवक डब्लू तकरीबन दो साल पहले काम करते बक्त छत से गिर पड़ा और उसकी रीट की हड्डी टूट गई। उसका परिवार खुम्खमी के कागर पर खड़ा है।

झारखंड में गरीबी रेखा (बोपीएल) से निचे के परिवारों को प्रति माह एक रुपया की दर से 35 किलो अनाज हासिल करने का हक है। लेकिन डब्लू मिंहं के परिवार के पास बोपीएल कार्ड नहीं है।

वहरहाल, भारतीय खाद्य निगम के गोदाम
एक बार फिर उसाठस भरे हुए हैं। लेकिन
उन्हीं से परिवारों की कमी नहीं।
नेशनल सैपल मर्वे के अनुसार, ग्रामीण
भारत के कुल ग्रीष्म परिवारों में से
लगभग इन आधे के पास बीपीएल कार्ड नहीं
है, तो क्यों न इन परिवारों को भी बीपीएल
कार्ड देकर उनमें अनाज बांट दिया जाए?
उन्हीं से कोई कमात्रा याच यही है कि
उसका दुख नजर में आ गया है। दुर्घटना के
तुरंत बाद स्वनें पहले उस पर स्थानीय
प्रक्रिया की नजर गई पिर जिला कलेक्टर
और बाद में स्थानीय विधायक तथा
बाकियों की। सबने माना कि फौरी राहत के
तौर पर उसे बीपीएल कार्ड मिलना चाहिए।

लेकिन प्रशासनिक दबू-पेच के कारण जब उसे बीपीएल कार्ड नहीं मिला, तो डब्लू के शुभचिंतकों ने यह मामाला रांझी से लेकर दिल्ली तक उत्तरा। जब सुनम कोट्टे के कम्पिन्सनों ने कमान सभाली और जिला कलेक्टर को तलब किया, तब जाकर उसने माना कि जिला प्रशासन डब्लू को बीपीएल कार्ड देने में लाचार है, क्योंकि इसके लिए किसी का नाम बीपीएल सूची से बाहर करना पड़ा। लोहावाल है कि जिले का बीपीएल कोटा निर्धारित है, इसलिए जिले की बीपीएल सूची से किसी का नाम हटाए और उसमें नया नाम जोड़ नहीं जा सकता। लोहावाल से दिल्ली तक फैली डब्लू के शुभचिंतकों की एक पूरी टोली के एक माल से ज्यादा की कोशिशें के बावजूद कठ

9
6

तमिलनाडु में
जिस गरीब को
रियायती दर पर
अनाज मिलता है,
वह झारखंड में
इस सुविधा से
वंचित क्यों है?

पसंदीदा दुकान से अब राशन लें या कैथ

सरकार ने नीलेकणि के फॉर्मूले को दी सैद्धांतिक मंजूरी

● अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के उपयोगकारियों को जल्द ही एक नई सुविधा मिलने वाली है। वे या तो रियायती राशन को अपनी पसंदीदा दुकान से खरीद सकेंगे या फिर इसके बदले नकद ले सकेंगे। पीडीएस में सुधार का यह फॉर्मला नंदन फोर्स ने सरकार को सुझाया है। सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर इन सुझावों को मंजरी भी दे दी है।

गड़बड़ी रोकने के लिए टास्क फोर्स ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और आधार कार्ड आधारित बैंक खातों के इस्तेमाल का भी फॉर्मूला मुशाया है। ये मुख्य टास्क फोर्स की ओर से तैयार 'आईटी स्ट्रेटजी फॉर द पीडीएस' को लेकर तैयार रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट बुधवार को वित्त मंत्री प्रणब मुख्यन के समझ पेश कर दी गई। प्रणब को रिपोर्ट सुनीपे के बाद यूआईटीआई के चेयरमैन नंदन नीलकण्ठ ने कहा कि सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। अब इस पर केरागा कि वे या तो वे राशन खरीदार के लिए अपनी पसंदीदा जगह, राशन की मात्रा और मिश्रण के बारे में बता सकते हैं या फिर वे राशन के मूल्य पर मिलने वाली सब्सिडी को रकम नकद ले सकते हैं। मौजूदा समय में पीडीएस उपभोक्ता केवल तथ्यशुदा दुकान से तथ्यशुदा मात्रा में ही राशन ले सकता है। देशभर में 4.62 लाख उचित मूल्य दुकानें हैं जिनके जरिए करीब 18 करोड़ परिवारों को 30 हजार करोड़ से ज्यादा कीमत के गेहूं, चावल, चीनी का वितरण किया जाता है।

अपने-अपने गरीब



सार्वजनिक वितरण प्राणी को बीपीएल सूची से ज्यादा बड़ा वितरण दिया है। यदि डबल टमिलनाडु, आधि प्रदेश या छत्तीसगढ़ में रह रहा होता, तो उसे इस अभिन्नीक्षा से नहीं गुजरना पड़ता। तमिलनाडु में पीडीएस सार्वजनिक है, वहां होके के पास राशन कार्ड है। आधि प्रदेश में सकारी नौकरी करने वाले को छोड़कर सबको राशन कार्ड स्कूलों में करवाना हो, तब भी इतके के ज्यादत धनी लोग शहर चले जाते हैं। गंवों में लोगांश मारे लोग या तो गरीब हैं या फिर गरीबी के कागार पर। फिर, स्थानीय प्रशासन इनां अकर्मण्य, भ्रष्ट और शोषक है कि न तो कोई विश्वसनीय बीपीएल संवेद्धण करा सकता है और न ही गरीबों को चिह्नित करने संबंधी कोई और काम।

के योग्य माना गया है। छत्तीसगढ़ में 'समावेश पद्धति' का इस्तेमाल होता है, लेकिन समावेश की कस्टोटी व्यापक है। जैसे वहाँ अनुसूचित जाति-जनजाति के सभी परिवारों का राशन कार्ड के योग्य माना गया है और पौधारी सभी के दायरे में लगाया 80 प्रीसेटी राशन आवादी शामिल है। फिर, राशन कार्ड की नियमित अंतर्गत पर सत्यपन होता है।

लातहार जैसे श्रावण इलाका में सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) पोडीएस की बड़ी जरूरत है। दरअसल टेकडायों और महाजनों को छोड़कर वहाँ कोई धनी आदमी नहीं है। अपने बच्चे का दाखिला तकिंग बेहतर ५८ निजी स्थानों के द्वायाएँ में भी कम दाम पर अनाज बेचना शुरू कर दिया है।

- लेखक जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता
और अर्थशास्त्री हैं।

मां होगी परिवार की मुखिया

राशन कार्ड में नाम ऊपर होगा, पैसा भी महिलाओं के नाम पर ही जारी होगा।

पंकज कुमार पांडेय | नई दिल्ली

सोनिया के दखल से माने मंत्रालय

पितृ प्रधान समाज की धारणा धीरे-धीरे बदल रही है। 'मेरे पास मा है' का गर्वाला फिल्मी संवाद अब यूपीए सरकार के एक महत्वपूर्ण कदम से घर-घर की कहानी बन सकता है। केंद्र सरकार ने तय किया है कि अब खाद्य सुरक्षा का लाभ देने के लिए बनने वाले राशन कार्ड में अनिवार्य रूप से पहला नाम 'मा' का होगा। मां के बाद ही परिवार के अन्य सदस्यों के नाम दर्ज किए जाएंगे। केंद्रीय खाद्य वितरण व नागरिक आपूर्ति मामलों के मंत्री केवी थॉमस ने भास्कर से खास बातचीत में इसकी पष्टि की।

उहोने कहा कि राशन कार्ड में अब किसी पुरुष का नाम पहले नहीं होगा। परिवार की मुखिया के तौर पर मां का नाम राशन कार्ड पर पहले दर्ज होगा। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अगर किसी परिवार को कोई धनराशि दी जाएगी तो वह भी महिला के नाम से ही भेजी जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रयास से केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून में महिलाओं से जुड़े सभी पहलुओं को खास तबज्जो दी है। एक अन्य अहम फैसले

थामस ने बताया कि दूध पिलाने वाली मां को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाने पर कुछ मंत्रालयों और राज्यों ने सवाल उठाए थे। पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दखल से यह मामला सुलझ गया है। दरअसल एक नवजात के लिए आहार उसकी मां के दूध से ही मिलता है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा के दायरे में दूध पिलाने वाली मां को लाना तर्किक है। कांग्रेस सूच मान रहे हैं कि अगर सरकार विधेयक शीतकालीन सत्र में लाती है तो इसका फायदा उसे पांच राज्यों के आसन्न विधानसभा चुनाव में भी मिल सकता है।

के तहत बच्चे को जन्म देने वाली मां को जन्म देने से लेकर छह माह की अवधि तक एक हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। कानून का अंतिम ड्राफ्ट मंत्रालयों की राय आने के बाद कैबिनेट में लाया जाएगा। थॉमस ने कहा कि सरकार इस विधेयक को शीतकालीन सत्र में लाना चाहती है, इसी दिशा में काम हो रहा है।

कानून तो मजबूत करिए सरकार

2012 में ऐसे प्रावधान लाए जाएं जिनमें बच्चों, स्त्रियों तथा वृद्धों की सुरक्षा और खुशहाली बढ़े। उन्हें उनके अधिकार बिना ज्यादा भेनत और मुकदमेबाजी किए भिले। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मुहिम की जरूरत है पर घर-परिवार, पास-पड़ोस, सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों में कमज़ोर लोगों को ज्यादा सुरक्षा एवं सद्भाव भिले; ऐसा सामाजिक ताना-बाना बुनने और सामाजिक बदलाव लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है।



■ कमलेश जैन

प्रसिद्ध अधिवक्ता

कानून के क्षेत्र में सन् 2012 का एंडोंडा क्या हो? इन्हें सारे कानून बन गए हैं कि खुद अधिवक्ता या न्यायाधीश भी याद नहीं रख पाते कि इनकी संख्या कितनी हैं और उनमें क्या लिखा है। फिर भी समाजिक रूप से बिछड़े और गरीब समाज को और भी कई कानूनों की जरूरत शिरदट से महसूस होती है।

अंतर किलिंग या रिश्तों की मौत की बात ही लीजिए। रोज कहीं न कहीं प्यार करने वालों को मौत के घाट उतारा जाता है। अपने ही रिस्तेदारों द्वारा पर किरण जा रहे इस कृत्य पर रोक लगाने के लिए कानून बनना मुश्किल है। सरकार अपने घोट बैंक की वित्त ज्यादा करती है, अपने नौजवानों की कम। विवाह आंधिनियम संशोधन बिल-2010-2011 में भी संसद में पेश नहीं हुआ। विवाह रजिस्ट्रेशन तक तत्वाक की प्रक्रिया इन्हीं कठिन क्यों है? इसे सरलीकृत करने के लिए ही यह बिल है। इसे जल्द पास होना चाहिए।

स्त्री के विरुद्ध अपराधों पर सशक्त कानून नहीं

भारत में हर वर्ष लाखों बच्चों को कोख में मार दिया जाता है। इसे रोकने के लिए प्री-कर्सेशन एंड प्री-नेटल डायनोस्टिक टेक्नीक्स (प्रोहिपिशन ऑफ सेक्स सलेक्शन) एक संशोधित-2003 है। इस कानून में गर्भस्थ बलिका का गर्भपात करने की अधिकतम सजा मात्र 3 वर्ष जबकि भारतीय दंड संहिता में अधिक महीनों के गर्भ को गर्भपात करवाने की सजा 7 वर्ष है या जीवित बच्चा होने से रोकने या ऐसा कुछ करने कि जिससे जन्म लेते ही बच्चा पर जाए की सजा 10 वर्ष है।

आश्चर्यजनक है कि हमारे यहां जिस विषय पर विशेष कानून बनते हैं (बच्चों और महिलाओं के लिए) तो वहां भारतीय दंड संहिता से कम सजा का प्रावधान होता है। विशेष कानून का अर्थ तो बुनियाद कानून से ज्यादा कड़ा होना चाहिए पर हमारे यहां उल्टी गांगा बह रही है। भार्ट संकीर्ण की धारा 354 जिसमें किसी लड़की से छेड़छाड़ की सजा मात्र दो वर्ष है (रुचिका राठोड़ मामला) को बढ़ाकर 5 वर्ष (आंप्र प्रदेश संशोधन 1991) की तरह या मध्य प्रदेश संशोधन-2004 की तरह 10 वर्ष तथा अमानवीय बनाया जाय। बलाकार से कुछ ही कम होने पर इस धारा का लाभ ले अपराधी जमानत लेकर अंत में रिहा या 2-3 महीने की सजा ही पाता है। लड़कियों में से कई रुचिका की तरह आत्महत्या भी करने पर मजबूर होती हैं।

बलाकार के मामलों में छानबीन (इवेस्टिगेशन) करने के लिए आपाराधिक प्रक्रिया सहिता में दिसम्बर 2009 में कापो ब्रेस्टोव किए गए जिससे पीड़ितों के घटना के बाद के संकट कम हो सके। जैसे पीड़ितों का बयान उसके घर पर, उसकी चुनी हुई जगह पर, उसके अपने लोगों के सामने होगा। गवाहों के बयान की आड़ियों वीडियो रिकार्डिंग होगी, जिससे वे अपने बयान न बदल पाए। पीड़ितों की डॉक्टरी जांच 24 घंटों के अंदर होगी। रिपोर्ट में विस्तर से सारी बातें लिखी जाएंगी। सुनवाई में अधियक्त पक्ष समय नहीं ले पाएगा या सुनवाई दो महीने से समाप्त होगी। खासकर बच्चों के मामलों में। पर मीडिया खुद ही देखे कि क्या इस संशोधन पर अदालत में लाया जा रहा है? ऐसा नहीं हो रहा। कारण इमरास्टर्कर्च ही नहीं है। यही हाल घरेलू हिंसा कानून का है। कानून फैसला दो महीनों में होना चाहिए पर दो साल से कई नहीं लगते।

बच्चों को जायदाद में बराबरी का अधिकार तो दे दिया गया है। पर आज जो सामाजिक परिवेश है, उसमें एक बेटी को मांगने पर ही उसका हिस्सा निकल सकता है, वह भी अदालतों के हस्तक्षेप पर। एक बार अगर वह यह कदम उठा लेती है तो उसके साथ रिश्ते मायके से सा पिता-भाई से खत्म हो जाते हैं। कभी-कभी उसका खून भी हो जाता है तो ऐसे में कानन में बदलाव यह हो कि प्रश्नान

उसे खुद उसका हिस्सा दिलवाने में मदद करे। जैसे कि घोरलू हिंसा कानून में सेवा प्रदाता या सुरक्षा अधिकारी उसे कानूनी मदद देते हैं।

अस्पताल, सिनेमा हॉल और मॉल्ट्स न बनें कब्रिगाह

जेल में पुलिस कस्टडी में होने वाली मौतों की तरह ही अब अस्पताल तथा सिनेमा हॉल भी कस्टेडिल मौतों की कब्रिगाह बनते जा रहे हैं। देश के तमाम अस्पतालों में बेसमेंट ज्वलनशील पदार्थ या ऑक्सीजन गैस सिलेंडर आदि रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक सापायरी डेट वाली या नकली दवाएं आराम से बेती खुरीदी जा रही हैं पर सख्त कानून की कमी है। सिनेमा हॉल हो मॉल, कहीं भी सुरक्षा कानून लचर है। उपहार सिनेमा कांड इसका जीता-जागता उदाहरण है। सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह एसीडी तथा लाईसेंस देने वालों को किसी भी प्रकार की लापरवाही से मुक्त कर उपहार के मालिकों की जुर्माना की राशि कम कर पीड़ितों का मुआवजा कम कर दिया है; वह भविष्य में आने वाले खतरों को दिखा रहा है। लोग आस लगाए बैठे हैं कि इन विषयों पर सख्त और सही कानून बने ताकि अस्पताल जाने वाले स्वस्थ होकर लौटे तथा सिनेमा देखने मॉल जाने वाले खुशी-खुशी घर आए।

बच्चों की हिंफाजत में चाहिए मजबूत कानून

एक अहम बिल-द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड प्रॉम सेक्सुअल अर्फेस बिल-2011 जो इस बार संसद में पेश होना था। वह जल्द से जल्द बनें। बच्चे चुराने वाले, बेचे खरीदने वाले या उन पर

शरीरिक-मानसिक अत्याचार करने वालों पर सख्त कानून बनें-उनकी सजा उदाहरणीय हो। हर शर्त में गिरोह चलाने वाले उन्हें अपाहिज कर भीख मंगवाते हैं। मामले पकड़ में आते हैं पर उसका नीति किसी को नहीं मालूम। ऐसा कोई मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में नहीं आता। सब कुछ निकले सर पर रका-दफा हो जाता है। वैसे भी बच्चों से भीख मंगवाने की अधिकतम सजा कुल 3 वर्ष है। यही सजा उन्हें शराब तथा नशे का आटी बनाने की भी है। बच्चों को माने, अकेला बाहर छोड़े, उनके साथ क्रूरता करने, मारने-पीटने की अधिकतम सजा मात्र छः महीने हैं। क्या यह ठीक है?

राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कम्प्लसरी एजुकेशन संशोधन बिल पास होने पर अस्म बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। स्कूल में एडमिशन के बत्त शिक्षा माफिया के रिस्ट्रिक्शन्स खत्म होने चाहिए। जैसे जन्म लेते बत्त सभी बच्चे समान हैं, वैसे ही स्कूल में एडमिशन लेते बत्त वे समान हैं। यही ध्यान में रखकर कानून बनाया जाना चाहिए ताकि प्राविट स्कूल शिक्षा देने वाले की जगह रुपया कमाने वाले केंद्र के रूप में न रहें। वहां सुरक्षा की निहायत कमी है। रैमिंग जारी है।

विधि से पुष्ट बने मातां-पिताओं की देखभाल

आए दिन हम अने आस-पड़ोस में देखे हैं कि मथुरा, बुन्दाबन, हरिद्वार, ऋषिकेश भरे पड़े हैं- ऐसे बुद्धों से जो अपनी संतान द्वारा बाहर निकाल दिए गए हैं। उन्हें लिए मेटेनेस एंड वेलेफर ऑफ पेरेन्ट्स एंड सीनियर सिटिजन्स एक्ट-2007 बना है। पर

इसका फायदा किनने लागे ले पाते हैं? इस एक्ट में प्रावधान है कोई भी उनकी तरफ से अदालत का आदेश आकर्षित कर सकता है। अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर अधिकतम सजा तीन महीने है। यानी 2-4 दिनों की सजा भी दी जा सकती है।

मेरी आशा है कि सन 2012 में सरकार ऐसे प्रावधान लाए जाएं जिसमें बच्चों, स्त्रियों तथा वृद्धों की सुरक्षा और खुशहाली बढ़े। उन्हें अनेक अधिकार बिना ज्यादा येहानत और मुकदमेबाजी किए भिले। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मुहिम की जरूरत है पर घर-परिवार, पास-पड़ोस सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों में कमज़ोर लोगों को ज्यादा सुरक्षा एवं सद्भाव मिले ऐसा सामाजिक ताना-बाना बुनने और सामाजिक बदलाव लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ़ कानून बनाना काफ़ी नहीं है। वैसे भी अदालती चबकर लगाकर त्वरित न्याय पाना टेढ़ी खिर है। पुनर्न बनाने पर अपली जामा चढ़े सन् 2012 के कामना यह भी है।

- **देश की 35 फीसद औरतों घरों में प्रताड़ित हैं**
- **39 फीसद पुरुष-औरतों दोनों पति द्वारा पत्नी की (कभी-कभी या हमेशा) पिटाई को सही मानते हैं**
- **10 फीसद औरतों यौन हिंसा की भी शिकार हैं**
- **63 फीसद औरतों घर में कोई फैसले लेने का अधिकार नहीं है**

ताकि मान-सम्मान के साथ नई जिंदगी मिले

अलका आर्य

लेखिका स्तंत्र
पत्रकार हैं।

दिल्ली उच्च अदालत की तख्त टिप्पणी और आदेश के बाद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अंततः दुर्कम्ह पीडित लड़कियों/महिलाओं की वित्तीय मदद के लिए बनाई गई योजना की घोषणा कर दी और जल्द ही इस पर अमल भी शुरू हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दुर्कम्ह पीडितों का मान-सम्मान लौटाकर नई जिंदगी की शुरूआत करने के मकसद से जो योजना तैयार की है, उसकी दरकार काफी समय से थी। ऐसी सहायता इंसाफ की बहाली को सुनिश्चित करने की दिशा में को जाने वाली कोशिशों का एक हिस्सा भर है। दो महीने पहले योजना आयोग ने केंद्रीय महिला - बाल मंत्रालय को लिखे एक पत्र में वह नोट भी नथी किया था कि अपाराधियों को सजा दिलाए जाने के साथ-साथ पीडित महिला की गरिमा एवं आत्मविश्वास का बहाल किया जाना भी जरूरी है।

यह उपचारात्मक न्याय का बह सिद्धांत है, जिसके आधार में पीडित महिला के उस सदमे से जिससे वह गुजरती है, को संवादित करना आवश्यक है और

सपोर्ट सेवाओं की जरूरत होती है। इस योजना के अनुसार बलाकार की हृ पीडित महिला को दो लाख रुपए की सहायता किसी में दी जाएगी। अगर वह नाबालिंग या मानसिक रूप से विकलांग या बलाकार के परिणामस्वरूप गर्भवती या इस पीडित हो जाए, तो यह सहायता तीन लाख रुपए होगी। पीडितों का स्वयं या उसकी ओर से मुकदमा दर्ज होने के 60 दिन के भीतर पुनर्वास बोर्ड में आवदेन देना होगा। दुर्कम्ह का मुकदमा दर्ज होने के 72 घंटे के भीतर पुलिस को रिपोर्ट पुनर्वास बोर्ड के सम्प्रश्न रखनी होगी।

हरबंश दीक्षित

४

सं चाना आधिकारी के दुरुपयोग पर एक बार बहस शुरू हो गई है। इस बार वहाँ की शुरूआत तबा न्यायपालिका सहित कुछ लोकद्रुक्तों की तरफ से भी समय-समय पर ऐसे सुझाव आते रहे हैं। जीते अगस्त में सुनील कोर्ट ने कहा था कि यदि इस कानून के दुरुपयोग को नहीं रोका गया, तो इससे बड़े समस्याएँ खड़ी हो जाएंगी। अदालत ने यह भी कहा कि कोई राष्ट्र यह नहीं चाहेगा कि सरकारी विभागों के 75 फीसदी समय में केवल सूचनाएँ देने में उलझे हों। इससे काम बहित होगा।

प्रधानमंत्री और शीर्ष अदालत की चिंता से सहमत होने वालों की अच्छी-खासी

संख्या है। सकारी दलरों में ते ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो इससे ब्रस्ट हैं। दूसरे कानूनों की तरह इस कानून के भी दुष्प्रयाग के मामले आ रहे हैं। कुछ जाहों भयादेहन का धीरघाव बनाने आई हैं। यदि सब कुछ इसी रहा, तो कुछ वर्षों में दरमी यामलों के निस्तारण में देरी कारण हवा कहना अप्रशंसनीय है। सूचना अधिकारी कानून ने समय में लोगों का जान खिलाफ किया है, जिससे कायाकर रखने चुनौतीय हैं। यह अभी सुरक्षा दीर में है, जिसे और मजबूत जरूरत है। इस कानून में सभी अपेक्षा की गई है कि वे अपने

बीच
बहस में

संबंधित तमाम जानकारियां इंटरनेट तथा अन्य माध्यमों से प्रकाशित करेंगे। इसे 12 अक्टूबर, 2005 तक ही पूरा किया जाना था, जो अब तक आशिक स्पष्ट से ही पूरा हो पाया है। इसके जबाबदेही भी सुनिश्चित नहीं की गई और जबाबदेह अधिकारी को दंडित किए जाना वाला था कि वह अपनी कार्रवाई भी नहीं है। यदि वाचित तारांग द्वारा उल्लंघन करा दी जाए, तो बहुत आपसियों का स्वतः राख रहे जाएंगा।

ट्रेटर अनुसार के मुताबिक, देश भर के नए आयुक्तों के यहां तीन लाख से ज्यादा मालिल लिख रहे हैं। इनका सभसे बड़ा जरूरत के अनुसार सूचना आयुक्तों अभाव है। सूचना अधिकारी कानून में गया है कि प्रत्येक राज्य में एक मुख्य ना आयुक्त तथा अधिकतम दस सूचना

आयुक्त होंगे। सूचना आयुक्तों की यह अधिकतम संख्या उत्तराखण्ड तथा छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्यों के लिए उत्तरायुक्त हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के लिए नाकामी है। कानून में सूचनाओं कर हर जिले के लिए कम से कम एक सूचना आयुक्त की नियुक्ति जरूरी है।

विलब का एक कारण यह भी है कि सूचना आयुक्तों के यांच विवाद निस्तरण की अधिकतम अवधि निरपेक्ष नहीं है, जबकि लोक सूचना अधिकारी के लिए तीस दिन तक प्रथम आपौलिय अधिकारी के लिए पैतालिस दिन का समय निरपेक्ष है। इसी का परिणाम है कि लोक सूचना अधिकारियों के समक्ष लंबित मामलों की संख्या नगम्य है, जबकि सूचना आयुक्तों के यांच लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है।

हुआ है ज्यायापालिका ने भी सूरु में खुद को इस कानून से अलग रखने की कोशिश की। सुरीम कोटे के ज्यायाधीशों की संपत्ति का व्याप हासिल करने के लिए सूचना अधिकार के कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अंततः ज्यायाधीशों की संपत्ति सूचना देने का फैसला आया, तो उससे पारदर्शिता के इस आंदोलन को एक नई दिशा मिली। इससे यह बहु भी सफ हो गया कि गोपनीयता का सुरक्षा कवच सबको समान रूप से समरोहित करता है।

दरअसल जनाधिकारों को सर्वसुलभ बनाने की पहल दोषारी तलवार की तरह होती है, जिससे एक और जनाधिकारों को नई परिभ्रामा मिलती है, दूसरी ओर उसके दुरुपयोग की आशकरण भी रहती है। कई बार दुरुपयोग की सूचनाएँ जो अतिरिक्त करके भी पेश किया जाता है। प्रभावशाली वांग इसे मोके के रूप में इत्येतत्वाल करके उसे कमज़ोर करने की कोशिश भी करता है। इसलिए एकत्रफ़ा बातों पर पूरी तरह भरोसा करना उचित नहीं है।

संभव है राष्ट्रीय स्तर पर शिकायत निवारण व्यवस्था

भारत डोगरा

लेखक स्तंभकार
हैं।

सूचना के अधिकार
के राष्ट्रीय अभियान
वे विकास

न शक्यता
निवारण कानून का
प्रक्रमानुसूची

एक ड्राफ्ट तयार
किया है, जो काफी
सराहा भी गया है।
इस बाब्त को

इस ड्रापट का तैयार करने में सूचना के अधिकार

के कानून के अनुभव से भी काफी सहायता मिल सकती है।

■ जगदानंद
सुचना आयुक्त, उडीसा

अभी तो पूरे प्रावधान ही लागू नहीं हुए

बुना अधिकार कानून को दो अहम डेवेलपमेंट्स से लाया किया गया था। पहला यह कि इससे व्यवसायों में शुद्धिता और जवाबदेही लाई जा सकी। जिससे पारदर्शिता बढ़े और फ्रेटवार्ट कम हो जाए। दूसरा कम कस्टम रह था कि जितनी सरकारी संस्थाएँ हैं वह परिवर्ती संस्थाएँ हैं, जो सरकार से मंददर्ती हैं और सरकारी द्वारा लातीनीकी की रही हैं, उन्हें अपनी-अपनी कार्यालयों और कार्यक्रम और समर्विष्ठ नियमों को 120 दिनों के अंदर वेबसाइट पर डालना था। इसके अलावा कोई भी नागरिक आग कोई सूचना चाहे तो उसे 30 दिनों के अंदर मुहूरा कराना था। छह साल बाद भी इस दूसरे घटना पर कानून काम रही थी।

अपर सकारी विधाया और संसदाएँ इस कानून को सही ढंग से पूरा कर लेती तो कई मामलों में सूक्षा मारे जाने की जरूरत ही नहीं होती। इस कानून के तहत पंचायत से लेकर संसद तक की कार्यपाली और कामकाज को कम्प्यूटराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। छोटे से लोट बड़े काम तक ऑफलाइन दस्तावेज बन जाता है, जिसे कोई भी इंटरनेट के जरिए देख सकता था तो लेकिन यह काम अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि समाज में आरटीआई एक्ट को लेकर एक माहौल जरूर बना है। सरकारी कामकाज पर गलती होने पर सवाल उठ रहे हैं। लोग बाप आरटीआई के जरिए सरकारी कामकाज के बारे में तह-तह के सवाल भी पूछ रहे हैं तो लेकिन यह बहरी इलाकों में कहीं जहां हो रहा है, देखा की ग्रामीण आवादी अब भी इस कानून का गूरा लाभ नहीं उठा सकता है। गांवों में चले जाना या फिर आदिवासी बहुल इलाकों में जाकर देखिए तो पता चलेगा वहां के लोगों को इस कानून के बारे में ज्ञान जानकारी नहीं है। जिन लोगों के पास योग्य-बहुत जानकारी है, उनमें भी यह समझ नहीं है कि इस कानून का इस्तेमाल कैसे करें? कहा से जानकारी मार्गें? कहाँ फैस जमा करीं हैं और कहा जानकारी कैसे इस्तेमाल होगी?

इसकी कवाह यही है कि सरकार को इस कानून का जितना प्रचार-प्रसार करना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है। इलाके कुछ राज्यों में इसको लेकर सराहनीय काम जरूर हुए हैं। मसलेन विधायक सभाकर ने अपने जातकारी सेवन की

माना जा रहा है कि विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों की नागरिकों के प्रति जिम्मेदारीयों को सम्पर्वद्य ढंग से रखायी जाए कि कौन सा कार्य इनको कितने समय पर पूरा करना है। इसके साथ ही यह व्यवस्था हो कि यह यह सम्पर्वद्य जिम्मेदारी पूरी नहीं की जाती है तो इसके लिए सम्पर्वद्य शिकायत निवापण प्रणाली विकसित की जाए।

इन मूल मान्यताओं के आगे कई सवाल हैं कि शिक्षायत निवारण व्यवस्था कितनी निष्पक्ष है व न्यायसंगत बन सकती व आम लोगों को शीघ्र न्याय प्राप्त करने की कितनी संभावना होगी। विशेषकर दूर-दूर के गांवों में व मन्धिन, कम शिक्षित परिवारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या उन तक भी इस शिक्षायत निवारण व्यवस्था का लाभ पहुंच पाएगा, जबकि शिक्षायत निवारण की सुधारें बड़ी जरूरत तो उन्होंने ही हैं।

है। जिस तरह सूचना के अधिकार के कानून में राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर सूचना आयोगों की स्थापना की व्यवस्था है वैसे इस ड्राफ्ट में शिकायत निवारण आयोगों की गत व केंद्र स्तर पर स्थापना की व्यवस्था है। शिकायत कानून के इस ड्राफ्ट में बताया गया है के देश के सभी ब्लॉकों या प्रबल्डों में शिकायत निवारण सम्हायता केंद्र स्थापित होने चाहिए, जो शिकायत निवारण के कार्य में आम लोगों विशेषकर कागज परिषिक्त व निर्धारित कर सकता है। सभी सार्वभौमिक प्रधिकारों में किसी अधिकारी को शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में व्यवसित किया जाए। इस शिकायत निवारण अधिकारी को नागरिक व संगठन सीधे अपनी शिकायत भेज सकते हैं या उनकी शिकायत ब्लॉक स्तर के शिकायत निवारण कार्यालय द्वारा भेजी जा सकती है।

की जिला स्तर के शिकायत निवारण कार्यालय में की जा सकती है। इस स्तर पर उमीद है कि शिकायत निवारण हो जाएगा। अधिकारी के दोषी पाए जाने पर सजा की व्यवस्था होती है। यदि भ्रात्याकार का मामला बनता है तो इकी अलग से जांच के लिए भेजा जाएगा। यदि यह आवश्यक समझा जाता है तो शिकायतकर्ता के लिए मुआवजे की व्यवस्था भी की जाएगी। जिला स्तर पर न्याय न मिलने पर राज्य व केंद्र स्तर के शिकायत निवारण आयोगों में अपील करने का प्रावधान भी इस ड्राफ्ट बिल में है।

इस ड्राफ्ट बिल की जानकारी अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न संस्थानों व नागरिकों के विचार इस बारे में प्रसार करने के लिए सम्मेलन, कार्यालयाता आदि का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न व्यवहारिक संदर्भों में घड़ करना कैसे कर्म

उम्मीद है कि शिकायत निवारण अधिकारी सम्पर्कबद्ध सीमा में शिकायत का संतोषजनक समाधान करेगा व जल्दत होने पर अधिकारी के लिए अनुकूल सज्जा की व्यवस्था भी करेगा, एर यदि उसके समय में कार्रवाई न की या उसके अद्वेष कार्यान्वयन न हो तो इसकी अपील शिकायत निवारण आयोगे कर सकता है, इसकी बहरत समझ बनोने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आवास, मनरोग, विजली, पानी, सामाजिक सुरक्षा, पचायत राज, पश्चवारण व वन आदि के संरचन में शिकायत निवारण प्रणाली कैसे कार्य करेगी। इस बारे में कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।

सरे लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, उसे लागू करने से योद्धे पल्ले से आप लोगों के इतेमाल के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। इससे आप लोगों की प्रतावित नियमों पर क्या प्रतिक्रिया होती है, इसका फीडबैक मिल जाएगा और इस फीडबैक के आधार पर कानून या नियम में तर्कसंगत बदलाव करना संभव होगा। यह भी अभी

— 2 —

ज्यादा सहज हो पाता।
इसके अलावा प्रत्येक सरकारी विभाग के लिए इस कानून की धारा 4 (1) के तहत यह भी प्रवधान है कि वह कामपक्ष प्रणाली के बारे में वह आमतोंगों को सूचना पट्टे के जरिए सुचित करें। मान लीजिए कि किसी को नगर निगम से अपने मकान का नवशा पास कराना है तो नगर निगम में इस बात की सूचना पहले से उपलब्ध होती चाहिए कि आपको मकान का नवशा कितने दिन के अंदर मंजूर होगा। तभी लोगों को किसी काम को लेकर दस्तरों के लगातार चक्रवर्क काटने और रिश्वत देने का मिलमिला बंद होता। यह काम अभी भी सरकारी टप्पों में नहीं ढाका है।

इस कानून के मुचार तरीके से लागू कराए के लिए देश भर में कमीशन बने हुए हैं। केंद्र में केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं तो राज्यों में भी सूचना आयुक्त हैं। इनके जिम्मे मुख्यतः दो काम हैं-एक तो मामलों को जल्दी से निपटने की व्यवस्था करनी है और दूसरी जिम्मेदारी यह है कि आरटीआई एक्ट के ऊपर भी निगरानी रखनी है। दूसरी जिम्मेदारी यह है कि आरटीआई एक्ट कैसे चल रहा है, इस पर सरकारों को अपनी रिपोर्ट देनी होती है। केंद्रीय सूचना आयुक्त हर साल संसद को अपनी रिपोर्ट देते हैं जबकि राज्य सूचना आयुक्त हर साल विधानसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। इन रिपोर्टों में सुझाव होते हैं, जिनके जरिए इस कानून को बेहतर बनाया जा सकता है। दुखर है कि अब तक इन रिपोर्टों पर ध्यान ही नहीं दिया है जबकि जरूरत इस बात की है कि इन रिपोर्टों के आधार पर एक एक्शन टेक्नेन रिपोर्ट हर साल पेश किया जाना चाहिए। वहहाल, यह एक ऐतिहासिक कानून है और इस पर निगरानी के लिए एक सक्रिय नागरिक समाज की जरूरत है।

क्या है सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून

- सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून 11, सितम्बर 1958 को संसद में पारित किया गया था। इस कानून की धारा 4 के तहत सेना को अशांत क्षेत्रों में शारारती तर्तों को गोली मार देने, बिना वारंट की तालाशी लेने या गिरफ्तार करने, सम्पति जब्त या नष्ट करने जैसे विशेषाधिकार प्राप्त हैं। इस कानून की धारा 6 के तहत केंद्र की अनुमति के बिना सशस्त्र बलों के खिलाफ किसी तरह का अधियोग नहीं लगाया जा सकता।
 - इस अधिनियम के तहत सरकर किसी क्षेत्र विशेष को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकती है। अगर वह इस नीति तक पहुंचती है कि उपरोक्त क्षेत्र या उसका एक ऐसी अशांत स्थिति में है कि नागरिक शासन की मदद के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल जरूरी है। सम्बन्धित प्रशासक ऐसे क्षेत्र या उसके किसी हिस्से को, जो किसी राय या केंद्रशासित प्रदेश का हिस्सा है, अशांत क्षेत्र घोषित कर सकता है। अधिनियम की धारा-वार किसी कमीशंड अफसर, वारंट अफसर या नान कमीशंड अधिकारी को ऐसे क्षेत्र में मिले अधिकार पर रोकी जाता है। धारा-छ बताती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत काम कर रहे किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ कानूनी कर्वाई केंद्र सरकर की अनुमति से ही संभव है। यानी किसी भी नागरिक को ऐसे किसी सैन्य अधिकारी द्वारा किए गए अमानवीय कर्य के विरुद्ध मुक्तमा घलाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का कोई अधिकार नहीं है।

कहाँ-कहाँ लागू है कानून

- सबसे पहले इसे पूर्वोत्तर के अंशान सेन्ट्रो में लागू किया गया था, जो पांच दशक बाद आज भी वह अस्तित्व में है। यह कानून 1958 से असम, मणिपुर, मेघालय, मिश्रिम, नगार्लैंड, निषुरा और अरुणाचल प्रदेश में लागू है। 1958 के कारीब मणिपुर में उत्तरवाद आम्बु हुआ। 1978 आरे-आते पूरे मणिपुर में उत्तरवाद परस्पर चुकाया था। वह तीस से अधिक उत्तराधी विद्यारथ्याएँ वाले समूह इस वक्त सक्रिय हैं। 1980 में पूरे राज्य को अंशान धौषित करके इस विशेष कानून को लागू कर दिया गया। सेना के उत्तरवाद विद्यार्थी अभियान और विशेष कानून को लागू करने के बावजूद उत्तराधी संस्थाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जनता के दशवां में राज्य के कुछ हिस्से से इस कानून को उत्तरा गया। 1980-90

पूर्वात्तर की अनसुनी आवाज

प्रभात कुमार रौय

मणिपुर में ईरंग चानू शर्मिला का विगत घारह वर्षों से जारी आपरण अनशन एक बार फिर उस समय राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया, जब उसने अना हजार के अनशन को अपनी द्विमायत प्रदान की।

1970 के दस्कं में जब ईराम शर्मित छोटी उम्र की ही थी, तभी मणिपुर में उत्तरावाद ने अपनी दस्कं दी। मणिपुर की पुस्तकून मगोस पहाड़ियों पर बैठकों और बृंदावनों के धमाके मूँजने लगे। नालंडॉ और मिजोराम की खुनों बाबात से प्रेरित मणिपुर के पृथक्तावादियों ने भी हथियार उत्तरकर हुक्मत-ए-हिंदुस्तान के खिलाफ जांग का एलान कर दिया। 22,350 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला मणिपुर दशक बीते-बीते पर्याप्त उत्तरवाद की चेपट में आ गया। इस

संसास्त्र विद्रोह पर काबू पान के लिए 1980 में राज्य में संसास्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (1958) लागू कर दिया गया। इस ऐक्ट के तहत सुख्खा बलों को वैसे विशेषाधिकार जाते हैं, जो सामिक्षणिक रूप से ऐक्ट के तहत पुलिस-प्रशासन गए हैं। इस ऐक्ट के तहत बिना पूछाड़, तलाशी एवं गिरावटारी अधिकार सुरक्षा बलों को मिले अलावा इसमें कारबाही को अंजाम सुख्खा बलों के अधिकारियों और किसी भी अदालत में मामला बनाया जा सकता।

इस अधिनियम से लैस सुरक्षा अधिकारियों और जवानों ने उन लड्डों हाथ कछु मामलों में कान-

बीच
बहस में

का भी उल्लंघन किया, जिसके कारण इस कानून के प्रति विरोध का स्वर प्रबल हुआ। मणिपुर से इस कानून को खत्म कराने के लिए ईरोम चानू शर्मिला ने दो नवंबर, 2000 से पर्याप्त अनशन शुरू किया, जो आज भी चाल रहा है। दरअसल आठवीं असम राहफल्ट्स जवानों ने मणिपुर के मालोम नामक न पर दस बेंगुनाह नागरिकों को अपनी नयों का शिकार बनाया था, जिसे देखकर शर्मिला को बेद्ध आघात लगा और ने अनशन शुरू कर दिया। पांच नवंबर, 2000 को पुलिस ने आत्महत्या का प्रयास के बीच अपरोप में उड़े गिरफतार कर लिया। इस से ईरोम शर्मिला की जिंदिया नाक छारा गी तो से दी जा रही तरल भोज्य पदार्थ पर रही है। कभी उड़े गिरफतार कर लिया गा है और कभी रिहा कर दिया जाता है।

दो अक्टूबर, 2006 को वह महात्मा गांधी की समाधि राजधानी भी पहुंची थी और राजधानी में अनेक सभाओं में भी शिरकत की थी। छह अक्टूबर, 2006 को दिल्ली परिसर ने उसे पिछे गिरफ्तार कर दिया।

केंद्र सरकार ने इस विभागादासन कानून की समीक्षा की जिम्मेदारी सुधार्म कोर्ट के विरिट जर हुक्म जस्टिस बीपी जीवन रेडी को समीक्षा। उहोने समाज से इस कानून को निपट करने की सिफारिश की, किंतु दुर्बाध्यवश जस्टिस रेडी की अनुशंसा को सुकराने ने नजर अंदाज कर दिया।

द असल अभी तक कायदे से उत तमाम हालात की समीक्षा भी नहीं की गई है, जिनके कारण तकनीकीन 25 लाख की आवादी वाले भाइपुर में उत्त्रावाह इस कठोर प्रवान चढ़ा कि उसे नियंत्रित करने के लिए फौज जलासी पड़ी। हालांकि पृथक तावादी अधियांसों में आमतौर पर हिंदू, और ईसाई नौजवान शामिल होते हैं, लेकिन हिंसक अलगावावादी बंगालत की प्रेरक शक्ति मजहब नहीं, बल्कि राज्य में फैला आर्थिक

असंगोले और शोषण-उत्पादन है। मणिपुर में प्रमुखता से भैंटी, पांगल, कुकी, नगा जनजातियाँ हैं। वैष्णव सप्तदाय की कृष्ण भक्ति से साथारोह मणिपुर के युवक अखिल सशस्त्र पृथकतावादी संग्राम से बचे जुड़े, यह एक जटिल प्रश्न है। पिछो से तीस वर्षों के दौरान तकरीबन तीस हजार जिंदगियों की बलि लेनेवाला यह उग्रवाद मूलतः प्रत के नौजवानों में व्याप्त भयावह बेरोजगारी और देश की आर्थिक सत्ता का कुछ हाथों में सिमटते चले जाने का कुरारिणाम है।

केंद्र सरकार और उत्का नेतृत्व के बीच संघर्ष विराम को लेकर हुए समझौते से असम में शांति की आशा जगी है। उम्मीद है कि मणिपुर के सशस्त्र बागी भी उत्का नेतृत्व का अनुसरण करेंगे तथा केंद्र सरकार भी गंभीरतापूर्वक इस विवादास्पद कानून को राज्य से हटाने पर विचार करेंगी। काश कि मणिपुर के सशस्त्र बागी ईरोम शर्मिला के अहिंसक संग्राम की शक्ति को पहचान पाते, और केंद्र सरकार अन्ना हजारे की तरह ईरोम शर्मिला की भी सुध लेते।

इरोम के अनशन को कब उचित मान मिलेगा।

कपाशंकर चौधे

लेखक टिप्पणीकार हैं।

यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं केवल अपना फर्ज निभा रही हूँ।' अपनी धोषणा के मुताबिक आज तक इरोम शर्मिला ने अपना अनशन नहीं तोड़ा है। अनशन पर बैठने के कारण इरोम शर्मिला पर पहली बार सन 2000 में अत्यधिक कोशिश का आरोप लगा और एक साल की जेल की सजा हुई। जेल में भी उनका अनशन जारी रहा। उसके बाद हर साल वे रिहा होती हैं और फिर अनशन पर बैठने के जुर्म में पुनः गिरफतार कर ली जाती हैं। स्वाधीन भारत में गांधी के बताए रखते पर अंदोलन को अपराध मानने के इस दृष्टिकोण को किस चीज़ की संज्ञा दी जाए?

11 साल के अनशन के दौरान इरोम शर्मिला ने स्वेच्छा से एक बुंद पानी भी नहीं पिया है। उनके हांठ सुखे हुए हैं। उनके नाक में नली लगी है जिससे फोर्स फिल्डिंग कर तत्स्व पदार्थ दिया जाता है। लंबे समय से अनशन के कारण इरोम शर्मिला का मासिक धर्म खत्म हो गया है। मणिपुर की जनता के लिए शर्मिला ने अपने मातृत्व का बलिदान किया है। न्यारह साल पहले इरोम शर्मिला ने जब अनशन शुरू किया था तो उनकी उम्र 28 साल थी। आज

39 साल है। पिछले 11 साल के दौरान इश्वर शर्मिला अपनी मां इश्वर शशि देवी से भी नहीं मिल पाई हैं। अपनी एक कविता में इश्वर शर्मिला ने कहा है, ‘अभी मौत मेरे दर नहीं आई, इसलिए मैं अपनी दृष्टि के आँखें में खांखालै देख सकती हूँ इत्तिहास के नए पथ पर लाल स्थापी से अधिक। इश्वर और कीड़ों के युद्ध में कहते हैं कि कीड़ों ने इश्वर की जान ले ली।’

निवासियों के हृदय को नहीं जीता जा सकता। 1949 में मणिपुर का भारत में विलय किया गया था।

संसद ने 1958 में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को पास किया था और उसे मणिपुर में लागू कर दिया गया। उसके बाद पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में इसे लागू कर दिया गया। इस कानून के तहत सिर्फ संदेह के आधार पर सुरक्षाबल किसी पर भी गोली चला सकते हैं, किसी के घर छापेराइ कर सकते हैं। कहने की जरूरत नहीं कि यह कानून अपने चरित्र में ही जनविरोधी है। इस कानून के दुरुपयोग के मामलों को देखकर और मणिपुर समेत पूर्वोत्तर के लोगों के हृदय की बाँधें सुनकर ही वहां अमन की उमीद जगाई जा सकती है। इरोम शर्मिला इसी अमन के इंतजार में है। बेहतर कल के इंतजार में। अपनी एक कविता में उन्होंने कहा भी है, ‘मैं तो शांति की सुगंध फैलाऊँगी। अपने जनस्थल खांगलैहै से। अनेकाले युगों में, यह सारी दुनिया में फैल जाएगी।’ देखना है कि शांति, न्याय और मानवाधिकारों के इरोम शर्मिला के संघर्ष को दिल्ली, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों और सिविल सोसाइटी की तरफ से कब उचित मान मिलता है।

हम कैसा **लोकपाल चाहते हैं**

जनलोकपाल और सरकारी लोकपाल दोनों ही मसौदे से हम असहभव हैं। सरकारी लोकपाल एक लंज-पुंज तथा कमज़ोर लोकपाल है। उससे भ्रष्टाचार खत्म करने की दिशा में कोई लाभ होता नज़र नहीं आ रहा। दूसरी ओर अन्ना हजारे और उनकी टीम का जनलोकपाल बहुत ज्यादा ताकतवर बनाए जाने के कारण उसके निरकुंश और भ्रष्ट हो जाने का खतरा है। इससे हमारा लोकतंत्र ही नष्ट हो सकता है। हमने अधिकार क्षेत्रों को पांच भागों में बांटे हुए वैकल्पिक लोकपाल का प्रारूप तैयार किया है। इसके पीछे हमारी मान्यता है कि शक्ति किसी एक ढांचे में केन्द्रित न होकर कई ढांचों में औजूद रहे ताकि निरकुंशता और तानाशाही का खतरा ही खत्म हो जाए। यहीं हमारे संविधान निर्माताओं ने भी चाहा था



मजदूर किसान शक्ति संगठन

दे श में प्रस्तावकर के खिलाफ जन मानस उद्दीपित और आवासित है, जिनमें प्रस्तावकर के विचार समाप्त हो जाए रहे हैं। स्वाक्षरित चर्चित विषय लेकपाल होने, जिससे प्रस्तावकर खत्म होने की उम्मीद को जा रही है। इस अभ्यास देश को जाना के साथमें प्रस्तावकर लेकपाल नामनुसार के नीन मसीदे हैं। एक मस्जिद स्करार का तथा दो मस्जिदे गाराहिंग समाप्त (सिरिलो-जोसावटी) की ओर से आ रहे हैं। एक परिषवक नोकवर्तमें यह समाय बाट है कि विवरणों की विविधता का समान हो, अपनी असशक्ति को प्रतिष्ठित करने की सबको जान दिले।

अग्र कोई पर्याय कह कि जो जनतोकपाल के साथ नहीं है, वह सरकार के साथ है तो यह दुर्बलियाँ है। इसलिए कि सरकार और अन्या हाथों के ठर भी लोगों के विचार ही सकते हैं तब तक उपर्युक्त करने का लोगों को उनमा ही हक़ है। लेकिन बाहरीयां ऐसा बताया जा रहा है कि जो आनंद के साथ नहीं है, वे खानों भ्रष्टाचार के पक्षपात्र हैं। इनमा ही नहीं, सूचना के जन अधिकार के रास्तों पर अभियान द्वारा तैयार किया गया वैकल्पिक लोकपाल के प्रारूप को स्विकृत सोसायटी में भर दार लाने वाला एक प्रयास बताया जा रहा है।

हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि न तो सरकार और न ही राष्ट्रीय सरकार परिषद का इससे कोई सरोकार है। वह पूरी तरह से सूचना ये जन अधिकारों के राष्ट्रीय अधिकारों द्वारा बास्तव में डायपट है, जिसे बनाने की काव्याद अन्ना हजारे के जंतर जंतर पर आयी थी। उनमें विभिन्न एवं अलग से ऐसे पूरी ही शुरू हो गए हैं। ठोंट अनन्त के कुछ सदस्य भी इसमें शुरूआती स्तर पर जुड़े हो थे।

हां, जनलोकपाल और सरकारी लोकपाल दोनों ही मसीद से हम असहमत हैं क्योंकि सरकारी लोकपाल एक तुंज-पुंज कमज़ार लोकपाल है, जिसके दायरे से प्रधानमंत्री को रखना रखा गया है तथा शिकायत करने के उसमें कोई प्रक्रिया ही नहीं रखी गई है। उल्टा शिकायत करने वालों को

ही हतोत्सवित करने का प्रावधान रखा गया है। वह यह कि शुद्धी शिकायतें पार्द जाने पर शिकायतकर्ता को 2 से वर्त 5 जेल की सजा और 25 हजार से 2 लाख रुपये तक जुर्माना का प्रावधान किया गया है। सरकार ने जो लोकप्रिय संसद के अधीनी संसदीय स्थानीय समिति की विवरणात्मक जाइश है, उससे प्रभालार खत्म करने की दिशा में कोई बदल नहीं आ रहा है।

दूसरी ओर अल्प हजारे और उनकी टीम की ओर से बनाए गए जनतोकपाल को बेहद ताकतवर बनाया गया है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका इन सबके ऊपर होता यह जनतोकपाल। यह पटवारी से लेकर प्रधानमंत्री तक सबकी शिकायत सुनेगा, मामले की जांच करेगा, सुनवाई करेगा

और दोष साकित होने पर सजा भी देगा। यह लोगों की निजता के अधिकार का हनन करके उनके फैलन टैप करेगा, एसएमएस और ई-मेल भी चेक करेगा तथा बिना व्यापारिक से बांट लिए रहनारी भी लेगा। टीम अन्ना का कहना है कि इनके द्वारा बनाया गया जनलोकपाल ही संरक्षित है तथा वे इससे कम कुछ भी स्वीकृत नहीं करेंगे।

जनस्कौलपाल से हमारी असहमति यह है कि इसे बहुत ज्ञाना तकनीकर बनाए जाने के कारण यह नियंत्रण और प्रश्न हो सकता है। इसके चलते हमारा लोकतंत्र ही बदल जाए सकता है। जिस प्रकार के जनस्कौलपाल की कल्पना की गई है, वह उनके काम के द्वारा भी व्याख्यात नहीं लगता है यहोकि यह संविधान से भी उपर शोधा जाता है इसे देख पर की शिक्षावाचक सुनाना का अधिकार भी दिया जाने से यह शिक्षावाचकों के बीच तंत्र लद भी सकता है।

वर्तमान इस प्रकार हम 'आतंकी' के आंदोलन नाम पर शक्ति के विकेन्द्रिकरण की हमारी संवैधानिक व्यवस्था, संसदीय जनतंत्र और संविधान की सर्वोच्चता पर अंगुली नहीं उठा रहे हैं? क्या हम दैव जैसा एक भवित्वविकाशील लोकप्रबन्ध करते हैं जो भ्रष्टाचार के साथ-साथ हमारे लोकतंत्र को ही खत्म करता है? सवाल है कि क्या हम इसे लोकतंत्र की कीमत पर स्वीकार करना चाहते हैं?

उपरोक्त लोकांत्रिक चिंताओं के मध्देनजर सूचना के जन अधिकार के राष्ट्रीय अभियान ने एक वैकल्पिक लोकपाल व्यवस्था प्रस्तुत की है। जो इस प्रकार हो सकती है-

- राष्ट्रीय भ्रातृत्वाचार निवारण लोकपाल - इस लोकपाल के द्वारे में प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, कर्कस्टर, एवं पी.आई.डी.के अफसर, कम्पनियों तथा गैर सकाराती संस्टन (एजन्जीओ) होंगे। यह उच्च स्तरीय भ्रातृत्वाचार को खत्म करेगा।
 - केन्द्रीय सतरकाता लोकपाल- वर्तमान में कार्रवात केन्द्रीय सतरकाता आयोग (सीरीसी) को स्वतंत्र किया जाए। उसके अधीन एक स्वतंत्र जीव एजेंसी काम करे। इसके द्वारे में द्वितीय श्रेणी के सम्पूर्ण अधिकारियों को लाया जाए तथा जांच के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं हो।
 - न्यायिक जवाबदी लोकपाल- सर्वोच्च न्यायालय के कई जाने-माने ईमानदार पूर्ण मुख्य न्यायालीयों का मानना है कि संविधान के मूलभूत उत्तरालोकों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि न्यायालिकाको स्वायत्ता को काम पर रखा जाए। न्यायालिकाको व्यापार भ्रातृत्वाचार के समाप्त करने के लिए सर्वोच्च मैट्रिक्स जवाबदी एवं व्यापार अधिकारियों विचारधीन है; पर इसमें बहुत कमियाँ हैं। इन्हें दुरुस्त कर विशेषक को शैक्षण्य प्राप्ति किया जाए। साथ ही एक 'न्यायिक जवाबदी' अधीन, जो ज्ञान न्यायालिकाको भ्रातृत्वाचार से मुक्त कर उसे जवाबदी बना सके।
 - शिकायत निवारण लोकपा�ल- भ्रातृत्वाचार एवं शिकायतों में फ़ैक है। इसलिए इनके निदान की प्रक्रिया एवं पद्धति भी अलग-अलग होंगी। भ्रातृत्वाचार निवारण का दांचा ऊपर से नीचे की ओर केन्द्रित स्थूल से काम करेगा। जांच की शिकायत निवारण का दांचा नीचे से ऊपर की ओर केन्द्रित रूप से काम करेगा। शिकायत सुनाए, जांच करेता तथा निवारण करने के लिए बैठक, शिकायत राज्य राज्यीय स्तर पर विवादान्वयन निवारण

लोकपाल का तीसरा मोर्चा

अन्ना हजारे के प्रस्तावित जनलोकपाल और संसद में पेश सरकारी लोकपाल पर दोनों पक्षों में जारी तनाती के बीच राष्ट्रीय सताहकार परिषद (एनएसी) से जुड़ीं समाजसेवी अरुणा राय के नेतृत्व वाले नेशनल कैम्पने फॉर पीपुल्स राइट टू इनकार्मशन (एनसीआरई) के वैकल्पिक लोकपाल का एक मसौदा पेश किया है। प्रस्तुत हैं उनके पांच मुख्य बिंदु-

1. केंद्र और प्रायोक राज्यों में लोकपाल/लोकायुत्तर (राष्ट्रीय/राज्य भृत्याचार निवारण लोकपक्ष) के गठन के लिए विद्युतक लाया जाए। इन लोकपाल/लोकायुत्तरों को सभी निवारित जनसमुदायों, प्रायोगिकमंडी, मुख्यमंडी, केंद्र व राज्यों के बीच संसद, विधायकसभा, विधानसभा आदि निवारित पार्टीजों अद्वारा वार्ष-अंते के सभी आलों असरसेरों के विविध भृत्याचार के मामले को स्वीकार करने, उनकी जांच करने और पर्याप्त साक्षात् पाये जाने की विधियां अधिकृतों पर मुकदमा घलाये जाने का पूरा विवरण दिया जाए। उन्हें ऐसे किसी भी व्यक्ति को खुलासा दिया जाए करने और उनके अधिकृतों पर मुकदमा घलाया कर पूरा अधिकार होगा, जो लोकपाल/लोकायुत्तर द्वारा को जो रही जांच या सुनवाई किया जा रहे किसी मामले में सहायतिपूर्वक है।

2. संसद में पेश होने वाले न्यायालिका जवाबदीयी और मानक विद्युतक में संवर्तन कर यह सुनिश्चित विवा जाए कि कार्यालयिकों से अपने स्वतंत्र अधिकारी और कार्यकर्ताओं में सत्यनिष्ठा से बिना कोई सुनिश्चित विवा न्यायालिका भी अस्वीकार और समन्वय रिकॉर्ड से अपनी जिम्मेदारी निभाये।

3. केंद्र और राज्यों में जन शिकायत लोकपाल (शिकायत विवारण विविध विधायक समिति) के गठन के लिए विद्युतक लाया जाए। इन लोकपाल/लोकायुत्तरों को सभी निवारित जनसमुदायों, प्रायोगिकमंडी, मुख्यमंडी, केंद्र व राज्यों के बीच संसद, विधायकसभा, विधानसभा आदि निवारित पार्टीजों अद्वारा वार्ष-अंते के सभी आलों असरसेरों के विविध भृत्याचार के मामले को स्वीकार करने, उनकी जांच करने और पर्याप्त साक्षात् पाये जाने की विधियां अधिकृतों पर मुकदमा घलाये जाने का पूरा विवरण दिया जाए। उन्हें ऐसे किसी भी व्यक्ति को खुलासा दिया जाए करने और उनके अधिकृतों पर मुकदमा घलाया कर पूरा अधिकार होगा, जो लोकपाल/लोकायुत्तर द्वारा को जो रही जांच या सुनवाई किया जा रहे किसी मामले में सहायतिपूर्वक है।

निवारण लोगोंमाला) के गठन और उनके कामकाज को सुनिश्चित करने वाले अधिनियमों का प्रास्प तैयार किया जायें। आयोगों को यह सुनिश्चित करने का अधिकार होगा कि हरके कार्यक्रमों द्वारा वित्तना नारिकर अधिकार पत्र (वार्डर) और उनके मानक तैयार किये जायें। वे यह भी तथ करोंगे कि अन्य हकदारी और अदिकार संस्थानोंबदल किये जा रहे हैं और प्रायोक सार्वजनिक प्रशिक्षण इन पर अभी कर रहे हैं। अधिकारात्मक सुनाई आयोग का कार्यपालीकरणी वाली संस्था होगा, जो हरके जीव और प्रबल स्तर पर होगा और यह मूलतः जट-केंद्रित ट्रॉफिकोन रखेगा ताकि शिकायतों का त्वरित गति तथा विकेन्द्रित सहभागी तथा पारदर्शी तरीके से निवारण किया जा सके। शिकायतों वाले प्रबल को सूचना के अधिकार करना चाहिया है बल्कि वे प्रबल कानून से भी संतुलन किया जा सकता है, जिसके तहत एक अवधि तक लोगों को चाहिए सेवा न देने पर संबंधी अधिकारियों पर जुर्माना लगाने का प्रबन्धन है। इस वारे में केवल शिकायत निवारण आयोग के अधिकार अभ्यन्तरीन कामों की ताप उत्तरा या सकता है।

4. केंद्रीय सरकार आयोग (सीवीआई) को और मजबूति दि जाए तथा इसकी जांच के दायरे में उन तमाम विभागों को दिया जाए, जिन्हें लोकप्राप्त विधेयक के तहत नहीं रखा गया। साथ ही इस संस्था को जांच और सुनवाई के अधिकार संसाधन दिये जायें। सीवीआई की तर्ज पर सभी सूची में सूची रखा जाएगा। आयोग का गठन किया जाये और विभागों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

जाति का विचार करने का नवाज़ा उपरांत आया।

5. मामले का घटावाहोड़े द्वारा बालों की सुरक्षा के असरकारी कानून बनाना होगा। इसके अलावा, प्रायोगिक सम्पदा को ऐसी सुरक्षा सूचना देने वालों की सुरक्षा उनकी पहचान गोपनीय रखने के प्रावधान करने होंगे। प्रायोगिक सम्पदा का एक प्रायोगिक पूरी परावर्तन करने के लिए होंगे। वे जिजबूत तथा प्रभावकारी जवाबदारी के उपरांत साथ अपनी सक्रियता (निषिक्रिया) के लिए अंतिम रूप जनता के प्रति जिम्मेदार होंगे। इन सभी समीक्षा कानूनों के अंतर्गत कामकाज के लिए जनता का सकारात्मक विचारण पर विचार किया जा सकता है। हालांकि सम्पदा का अवश्य ही अलग और स्वतंत्र रहे।

गोट : देशी सुनी के विषय में अपने जुङ्गाव, जंकथा व कार्य में इसकी उपयोगिता और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें। ताकि हम आपके लिये इसका प्रकाशन व वितरण जारी रख सकें।

ଜାଗୋରି
JAGORI

जागरा बा-114 शवालाक मालवाय नगर, नझ दिल्ली-110017,
फोन: 26691219, 26691220
email: resource@jagori.org/jagori@jagori.org